www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 5 मार्च, 2024

दैनिक जागरण

संयम की तटरेखा कई संकटों से बचा लेती है

सराहनीय फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों और सांसदों को सदन के अंदर भाषण या वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर आपराधिक मामले से छूट देने के 1998 के अपने फैसले को पलटकर बिल्कुल सही किया। ऐसे किसी फैसले की आवश्यकता इसलिए थी, क्योंकि यह छूट लोकतांत्रिक मूल्यों-मर्यादाओं का मुंह चिढ़ाने वाली तो थी ही, उसका बेजा लाभ भी उठाया जा रहा था। इसका एक प्रमाण तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा हैं, जिनकी कुछ समय पहले लोकसभा सदस्यता इसलिए रद हुई, क्योंकि वह उपहार लेकर संसद में सवाल पूछने की दोषी पाई गईं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनके खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है। जो भी हो, यह किसी से छिपा नहीं कि इसके पहले भी कुछ सांसद पैसे के बदले सवाल पूछने के आरोपों से दो-चार हो चुके हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि विधान परिषद और राज्यसभा के चुनावों में पैसे लेकर वोट देने के मामले सामने आते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से झारखंड मुक्ति मोर्चे की विधायक सीता सोरेन की मुश्किलें बढ़ना तय है। उन पर आरोप है कि 2012 में राज्यसभा के चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को वोट देने के बदले उन्होंने रिश्वत ली थी।

सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से अपने जिस फैसले को पलटा, वह फैसला भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उन सांसदों के मामले में तीन-दो के बहुमत से आया था, जिन पर यह आरोप था कि उन्होंने 1993 में नरसिंह राव सरकार के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान रिश्वत लेकर सरकार के पक्ष में वोट दिया। बाद में यह आरोप सही पाया गया और सीबीआइ की जांच में यह भी साबित हो गया कि कितने पैसे किसके खाते में पहुंचे। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उसने यह तो माना कि रिश्वत लेकर वोट देने वाले सांसदों ने उनके भरोसे का सौदा किया है, जिनका वह प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वे उस विशेषाधिकार के चलते सुरक्षा के अधिकारी हैं, जो संविधान ने उन्हें प्रदान किया है। इस फैसले के चलते विधायकों और सांसदों को एक तरह से मनमानी करने की छूट मिल गई। विधायकों और सांसदों को विशेषाधिकार इसलिए मिले हैं, ताकि वे सदन में बिना किसी भय-संकोच अपनी बात कह सकें। दुर्भाग्य से इस विशेषाधिकार की मनचाही व्याख्या करते हुए यह मान लिया गया कि विधायक-सांसद सदन में कुछ भी कर सकते हैं और यहां तक कि पैसे लेकर सवाल पूछने के साथ मतदान भी कर सकते हैं। अच्छा हुआ कि अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसमें संदेह है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राजनीति में शुचिता को स्थापित कर सकेगा। इस संदेह का कारण यह है कि अभी हाल में उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में क्रास वोटिंग हुई। भले ही इसके पीछे पैसे की भूमिका न हो, लेकिन वह राजनीतिक अनैतिकता तो है ही।

किसानों की कठिनाई

पंजाब में गत दो दिन में हुई वर्षा और ओलावृष्टि ने किसानों की कठिनाई बढ़ा दी है। मौसम की मार से खासतौर पर सरसों और गेहूं की फसल को भारी क्षति पहुंचने की आशंका व्यक्त की जा रही है। एक अनुमान के अनुसार सात सौ एकड़ रकबे में सरसों की पूरी फसल खराब हो गई है, जबकि बड़े रकबे में गेहूं की बालियां टूट गई हैं। किसानों की मुश्किलें इसलिए और बढ़ गई हैं, क्योंकि गत वर्ष मानसून के दौरान बाढ़ आने से भी कई जिलों में फसलें बर्बाद हो गई थीं। इसलिए यह आवश्यक है कि वर्षा और ओलावृष्टि से हुई क्षति से किसानों को उबारने के लिए सरकार शीघ्रता से प्रयास आरंभ करे। खराब हुई फसलों का आकलन करने के लिए शीघ्र गिरदावरी का प्रबंध किया जाना चाहिए। पहले ऐसा देखा गया है कि गिरदावरी करने में और उसकी रिपोर्ट आने में बहुत समय लग जाता है। इसके बाद मुआवजे के लिए भी किसानों को जूझना पड़ता है। ऐसे भी मामले सामने आ चुके हैं जब मुआवजे के नाम पर बहुत ही छोटी राशि देकर किसानों के साथ भद्दा मजाक किया गया है। समय पर सहायता नहीं मिलने पर किसान अक्सर कर्ज के जाल में फंसने पर मजबूर हो जाता है। सरकार और प्रशासन को इन बातों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। गिरदावरी तो शीघ्र शुरू की ही जानी चाहिए, मुआवजा बांटने की पूरी प्रक्रिया में भी पर्याप्त पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। सरकार का प्रयास यही होना चाहिए कि किसानों को समय पर उचित सहायता मिल सके। इसके लिए केंद्र से भी यदि सहयोग अपेक्षित हो तो उसे लेने में संकोच नहीं किया जाना चाहिए।

> मुआवजा बांटने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रयास यही होना चाहिए कि किसानों को समय पर उचित सहायता मिल सके

आंतरिक संकट की अनदेखी के दुष्परिणाम

राज कुमार सिंह

गुटबाजी कांग्रेस के राजनीतिक चरित्र का हिस्सा रही है, पर आलाकमान और वरिष्ठ प्रादेशिक नेताओं के बीच आज जैसी संवादहीनता कभी नहीं रही

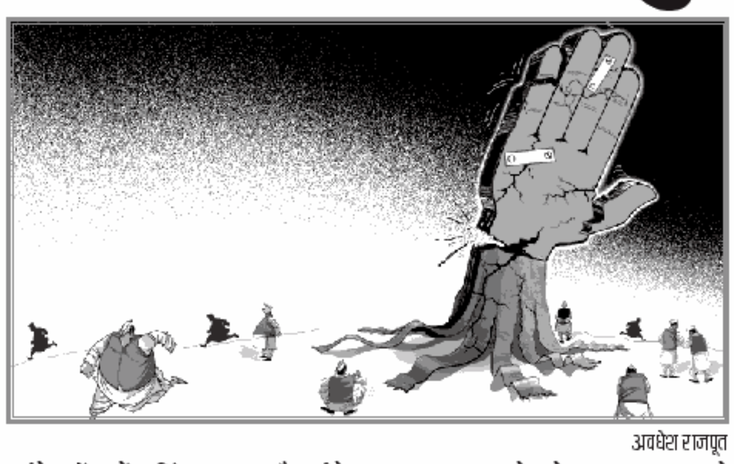

अवधेश राजपूत

हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया द्वारा कांग्रेस के छह बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने से राज्य में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को तात्कालिक तौर पर जीवनदान मिल गया। सरकार को संकट से उबारने के लिए कांग्रेस आलाकमान के रवैये की प्रशंसा की जा सकती है, लेकिन सवाल यह भी है कि ऐसी स्थिति निर्मित कैसे हुई? यदि वहां के हालात पर पहले मंथन किया गया होता तो आवश्यक वोट होने के बावजूद राज्यसभा सीट हारने की फजीहत नहीं होती। 2022 के विधानसभा चुनाव में 40 सीटें जीतकर कांग्रेस ने सुविधाजनक बहुमत हासिल किया और भाजपा 25 सीटों पर सिमट गई। हालांकि दोनों को मिले वोटों में एक प्रतिशत का ही अंतर रहा। ऐसे बहुमत के बावजूद मुख्यमंत्री चयन के लिए जैसी रस्साकशी हुई, वह कांग्रेस में गुटबाजी का स्पष्ट संकेत थी।

यह कोई दबी-छिपी बात नहीं कि हिमाचल में कांग्रेस की राजनीति दशकों तक वीरभद्र सिंह के इर्दगिर्द घूमती रही। पीवी नरसिंह राव के करीबी समझे गए वीरभद्र के गांधी परिवार से रिश्ते सहज नहीं रहे, लेकिन उनके बिना हिमाचल में कांग्रेस सरकार की कल्पना भी तब मुश्किल नजर आती थी। वीरभद्र सिंह के निधन के बाद हुए पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलते ही आलाकमान ने पार्टी को उनके परिवार के कब्जे से निकालने की रणनीति बना ली। वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं और मंडी से लोकसभा सदस्य भी। प्रतिभा मुख्यमंत्री बनना चाहती थीं, क्योंकि बेटा विक्रमादित्य ज्यादा अनुभवी नहीं, मगर आलाकमान उनके विरोधी और अपने विश्वस्त सुखविंदर सिंह की ताजपोशी में सफल रहा। संतुलन की कवायद में मुकेश अग्निहोत्री को उपमुख्यमंत्री और विक्रमादित्य को मंत्री बनाया गया, लेकिन गुटबाजी पनपती रही। प्रतिभा गुट के विधायक विभिन्न मामलों में पत्र लिख कर सुक्खू पर दबाव बनाते रहे, लेकिन ज्यादा सुनवाई नहीं हुई। क्रास वोटिंग करने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने पर प्रतिभा सिंह ने कहा भी कि अगर उनकी शिकायतों का समय रहते समाधान किया गया होता तो नौबत यहां तक नहीं पहुंचती। सुक्खू की छवि साफ-सुथरी है, पर अपने ही विधायकों की बात न सुनना-समझना राजनीतिक कौशल का परिचायक तो नहीं। बेशक यह सब आलाकमान की भी जानकारी में था। इसलिए बात के बगावत तक पहुंच जाने के लिए वह भी जिम्मेदार हैं।

संकटमोचक बनाकर भेजे गए पर्यवेक्षकों भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिवकुमार ने सब कुछ ठीक होने का दावा किया है, लेकिन उस पर भरोसा आसान नहीं। एक तो जिन विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया है, वे प्रतिभा गुट के हैं। जाहिर है, उनकी शह पर ही सब कुछ हुआ होगा। ऐसे में क्या वह गुट शांत बैठकर अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता पर ही सवालिया निशान लगाएगा? ध्यान रहे कि भाजपा खुलकर कह चुकी है कि वह अयोग्य घोषित विधायकों के साथ खड़ी रहेगी। विधानसभा की प्रभावी संख्या 62 रह जाने के बाद बहुमत का आंकड़ा 32 बनता है, जबकि कांग्रेस के पास 34 विधायक बचे हैं। यह सुविधाजनक बहुमत तो कतई नहीं। भाजपा और प्रतिभा मिलकर कभी भी सुक्खू के 'सुख' पर ग्रहण लगा सकते हैं। सुक्खू सरकार को मिली राहत के बावजूद कांग्रेस के राजनीतिक प्रबंधन पर उठते सवाल जवाब मांगते रहेंगे। हिमाचल से पहले कमल नाथ और सचिन पायलट ही ऐसे दो प्रकरण रहे, जब आलाकमान ने अपनी सक्रियता से संकट टाल दिया, लेकिन हर बार वह बहुत देर से जागा। इसका उसे कई राज्यों में नुकसान भी उठाना पड़ा।

2000 में समर्थक विधायकों समेत ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने से मध्य प्रदेश में जिन कमल नाथ की सरकार गिर गई थी, वह पिछले महीने जब भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच समर्थक विधायकों समेत दिल्ली पहुंच गए, तब कांग्रेस जागी। कमल नाथ को कभी इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कहा जाता था तो सिंधिया की गिनती राहुल-प्रियंका के करीबियों में होती थी। अगर गांधी परिवार के इतने करीबियों से संपर्क-संवाद का यह हाल है तो बाकी कांग्रेस नेताओं के हाल की कल्पना आप कर सकते हैं। हिमंत बिस्वा सरमा से जुड़ा एक किस्सा आज भी सुनाया जाता है कि कैसे कई दिन दिल्ली में रहने के बाद भी उन्हें कांग्रेस आलाकमान ने भाव नहीं दिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल में तो संकट विस्फोटक स्थिति में पहुंच गया, मगर अन्य राज्यों में भी कांग्रेस में सब कुछ सामान्य नहीं है। यह सच है कि गुटबाजी कांग्रेस के राजनीतिक चरित्र का हिस्सा रही है, लेकिन आलाकमान और वरिष्ठ प्रादेशिक नेताओं के बीच ऐसी संपर्कहीनता और संवादहीनता कभी नहीं रही। बेशक एक ऐसा राजनीतिक प्रबंधन तंत्र भी हमेशा रहा, जो देश से लेकर प्रदेशों तक कांग्रेस नेताओं पर नजर रखता था, ताकि बीमारी गंभीर होने से पहले ही उसका जरूरी उपचार किया जा सके।

लगता है अहमद पटेल के निधन के बाद कांग्रेस में कोई राजनीतिक प्रबंधन व्यवस्था नहीं रह गई है। अगर है भी तो वह प्रभावी तो नहीं दिखती। किसी एक मठाधीश के हवाले पूरे राज्य की राजनीति छोड़ दी गई है और बाकी नेता उसकी कृपा पर निर्भर हैं। जाहिर है, ये मठाधीश अपने परिजनों एवं करीबियों के अलावा किसी और नेता को पनपने नहीं देते। परिणामस्वरूप आलाकमान की उन पर निर्भरता लगातार बढ़ती जाती है। यह स्थिति कांग्रेस संगठन को तो राज्य-दर-राज्य खोखला कर ही रही है, आलाकमान की कमान भी कमजोर पड़ रही है और क्षत्रप उसे आंखें दिखाने में संकोच नहीं करते। अब जब लगातार सिकुड़ते हुए कांग्रेस ज्यादातर प्रदेशों में हाशिये पर पहुंच गई है, तब यह सवाल से उठता है कि आखिर कांग्रेस आलाकमान व्यस्त कहां रहता है कि उसके पास अपने बड़े नेताओं से भी संपर्क और संवाद का समय नहीं? दूसरी ओर भाजपा है जो शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह सरीखे क्षत्रपों को बदलने में संकोच नहीं करती। उसका आलाकमान अपने दल ही नहीं, दूसरे दलों के नेताओं से मुलाकात के लिए सहज उपलब्ध रहता है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

गेहूं-धान के दुष्चक्र से निकलें किसान

रमेश कुमार दुबे

पंजाब आदि राज्य सरकारें गेहूं-धान की खेती को प्रोत्साहन देकर देश में असंतुलित कृषि को बढ़ावा दे रही हैं

फसल विविधीकरण को अपनाएं किसान। फाइल

किसान आंदोलन का अंत कब होगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इस आंदोलन ने खेती-किसानी की बदहाली और किसानों के नाम पर की जाने वाली राजनीति को उजागर करने का काम किया है। कांग्रेस आज कह रही है कि यदि वह सत्ता में आती है तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सरकारी खरीद की गारंटी देगी। ध्यान रहे कि 2004 से 2014 के बीच केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में संप्रग की सरकार थी। उसने एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया था। आयोग ने 2004 से 2006 के बीच पांच सिफारिशें की थीं, जिन्हें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। उसकी सबसे अहम सिफारिश थी कि सरकार किसानों से उनकी फसलों को लागत मूल्य से डेढ़ गुना अधिक कीमत देकर खरीदे। आयोग ने इसके साथ-साथ भूमि सुधार, सिंचाई, खाद्य सुरक्षा, कृषि बाजार के उदारीकरण और किसानों के ऋण एवं बीमा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की सिफारिश की थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उसकी सिफारिशों को अव्यावहारिक बताते हुए लागू करने से इन्कार कर दिया।

यद्यपि देश भर के किसान तमाम चुनौतियों से जूझते हैं, लेकिन आंदोलन करने वालों में पंजाब के किसानों की अधिकता है। इसकी जड़ सरकार की एकांगी खरीद नीतियों में निहित है। यद्यपि सरकार 23 फसलों के लिए एमएसपी घोषित करती है, लेकिन कुछ साल पहले तक यह सरकारी खरीद गेहूं-धान जैसी कुछेक फसलों और पंजाब-हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे चुनिंदा इलाकों तक सिमटी रहती थी। एमएसपी की शुरुआत पिछली सदी के सातवें दशक में तब हुई, जब देश में अनाज का संकट था। तब सरकार ने जिन इलाकों में बेहतर कृषिगत ढांचा मौजूद था, वहां के किसानों को विश्वास दिलाया कि उनकी उपज को सरकार द्वारा तय कीमत पर खरीदा जाएगा, भले ही अनाज की कीमत कितनी भी कम क्यों न हो जाए। इसका परिणाम यह हुआ कि पंजाब-हरियाणा में गेहूं-धान केंद्रित कृषि को बढ़ावा मिला और देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना। इस उपलब्धि के लिए पंजाब को देश के खाद्य-कटोरे की उपाधि दी गई। पंजाब में धीरे-धीरे किसानों-आढ़तियों की ताकतवर लाबी का विकास हुआ, जिसने राजनीतिक दलों और सरकारों पर गेहूं-धान के एमएसपी में बढ़ोतरी और अधिकाधिक सरकारी खरीद के लिए दबाव बनाया। राजनीतिक दलों और सरकारों ने भी गेहूं-धान के सहारे अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए मुफ्त बिजली-पानी का पासा फेंका। इसका नतीजा यह हुआ कि पंजाब की परंपरागत फसलें पीछे छूट गईं। इससे फसल चक्र रुका और जमीन की उर्वरता से घटी, जिसकी भरपाई के लिए रासायनिक उर्वरकों-कीटनाशकों का इस्तेमाल होने लगा। इससे खेती की लागत बढ़ी और लागत के अनुरूप कीमत न मिलने से गेहूं-धान की खेती घाटे का सौदा बन गई। गेहूं-धान की सरकारी खरीद का एक नतीजा यह निकला कि पंजाब के किसानों को मक्का, कपास और मूंग जैसी फसलें एमएसपी से कम कीमत पर बेचने के लिए विवश होना पड़ता है।

पंजाब में गेहूं-धान जैसी पानी की अधिक खपत वाली फसलों को बढ़ावा देने से जल स्तर घटता जा रहा है। 2018 में प्रकाशित पंजाब सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 79 प्रतिशत इलाकों में भूजल अतिदोहन की श्रेणी में आ चुका है और यहां 2039 तक भूजल खत्म हो जाएगा। 2020 में केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा पंजाब में भूजल के ब्लाकवार सर्वे में भी खतरनाक संकेत सामने आए। विडंबना ही है कि पंजाब के संकट से सबक सीखने के बजाय दूसरे राज्य बोनस देकर गेहूं-धान की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं जैसे मध्य प्रदेश में गेहूं और छत्तीसगढ़ में धान। इससे असंतुलित कृषि को बढ़ावा मिल रहा है। कृषि विशेषज्ञों का सुझाव है कि पंजाब को गेहूं-धान के दुष्चक्र से निकाला जाए, पर ठोस प्रयास न होने से किसान मजबूरन गेहूं-धान के कुचक्र में उलझे हुए हैं। अब मोदी सरकार देश की पारिस्थितिक दशाओं के अनुरूप फसल चक्र विकसित कर रही है। इसीलिए बीते एक दशक में सरकार ने गेहूं-धान की तुलना में मोटे अनाजों, दलहनी-तिलहनी फसलों के एमएसपी में भरपूर बढ़ोतरी की है। इसके साथ-साथ सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, झारखंड आदि उन इलाकों में एमएसपी पर सरकारी खरीद का नेटवर्क स्थापित कर रही है, जहां अभी तक एमएसपी पर खरीद का नामोनिशान तक नहीं है।

इसे भी विडंबना ही कहा जाएगा कि देश में अनाज ग्रामीण क्षेत्रों में पैदा होता है, लेकिन उसका भंडारण शहरी क्षेत्रों में होता है। फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित करने के लिए इसका देशव्यापी परिवहन किया जाता है। इससे न केवल ढुलाई लागत बढ़ती है, बल्कि अनाज की बर्बादी भी होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, फसलों के नुकसान को कम करने के साथ-साथ फसलों की खरीद-बिक्री का विकेंद्रित तंत्र स्थापित करना है। चूंकि पंजाब में गेहूं-धान की खरीद-बिक्री पर बड़े किसानों और आढ़तियों का वर्चस्व है, इसलिए कृषि विपणन सुधारों और फसल विविधीकरण के प्रयासों का सबसे ज्यादा विरोध पंजाब में होता रहा है। मौजूदा आंदोलन में पंजाब के किसानों की भागीदारी का एक कारण यह भी है।

(लेखक एमएसएमई मंत्रालय के निर्यात संवर्द्धन एवं विश्व व्यापार संगठन प्रभाग में अधिकारी हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

मृत्यु

यदि जन्म है तो मृत्यु भी है। मृत्यु संसार का शाश्वत सत्य है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, 'मृत्यु जीवन के साथ ही चलती है, वह जीवन के साथ ही बैठी है और सुदूरवर्ती पथ पर भी जीवन के साथ-साथ जाकर साथ ही लौट आती है।' व्यक्ति जीवनपर्यंत जीव-जगत के प्रपंचों में पड़ा कर्मरत रहता है। वह प्रत्यक्षतः तो जीवन जीता प्रतीत होता है, पर परोक्ष रूप से मृत्यु हर क्षण उसके साथ रहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मृत्यु जीवन की सहचारी है। वह जीवन के साथ आती है और जीवन को साथ लेकर ही जाती है।

सांसारिक मनुष्य मृत्यु को भय मानते हैं। आखिर ऐसा हो भी क्यों न? मृत्यु तो हमेशा दबे पांव आती है। वह कोई चेतावनी नहीं देती, बल्कि चुपचाप आकर अपने पंजे में जीवन को जकड़ लेती है। उस पर किसी का जोर नहीं चलता। ठीक वैसे ही जैसे कोई बिल्ली जब दबे पांव आकर चूहे को दबोच लेती है तब बिल्ली द्वारा दबोच लिए जाने पर चूहे का कोई जोर नहीं चलता। न ही उसके साथियों का या बंधु-बांधवों का कोई जोर चलता है। कुछ लोग इसीलिए मृत्यु को क्रूर कहते हैं। भगवान बुद्ध जन्म-मरण को दुख मानते हैं। दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टि से वह इस दुख से निवृत्ति का मार्ग सुझाते हैं। संपूर्ण भारतीय दर्शन भी अमृत्व की बात करता है। वह आत्मा की अमरता की बात करता है। श्रीमद्भगवद्गीता मृत्यु को एक विश्राम स्थल मानती है। वहीं अथर्ववेद कहता है कि तमेव विद्वान् न विभाय मृत्योः। अर्थात आत्मा को जानने पर मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता।

आत्मा की अमरता में विश्वास करने वाला भारतीय दर्शन सामान्यतः मृत्यु में भौतिक शरीर के नाश की बात करता है। वहीं संसार में मृत्यु के बाद भी यश काया जीवित रहती है। अतः साधारण वैचारिक दृष्टिकोण से अपकीर्ति मृत्यु है। निस्पृह, आध्यात्मिक, पाप और वासना रहित जीवन जी कर मृत्यु के भय से मुक्ति पाई जा सकती है।

डा. प्रशांत अग्निहोत्री

वन्य जीवों के संरक्षण की पहल

अली खान

> पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित और प्रकृति के सौंदर्य को बनाए रखने के लिए वन्य जीवों का संरक्षण जरूरी है

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, वर्तमान में देशभर में करीब 13,874 तेंदुए हैं। यह जैव विविधता के प्रति भारत के अटूट समर्पण का प्रमाण है। केंद्र सरकार ने जानवरों की सात प्रजातियों के संरक्षण के लिए हाल में एक इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस बनाया है। बिग कैट के अंतर्गत मुख्यतः सात जानवर आते हैं। इनमें प्रमुखतः बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता शामिल हैं। इस एलायंस की सफलता के लिए बहुत जरूरी है कि देश-दुनिया में वन्य जीवों के लिए एक मुफीद वातावरण बनाया जाए। उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए बेहतर प्रबंध किए जाएं।

पिछले एक दशक से यह अनुभव किया गया है कि जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक विकास और अनियंत्रित शहरीकरण के कारण वन्य-जीवों के प्रवास क्षेत्र का लगातार ह्रास हो रहा है। इसके फलस्वरूप आसपास रहने वाले लोग वन्य जीवों की चपेट में आ रहे हैं। बेतहाशा शहरीकरण और खत्म होते जंगल ने जंगली जानवरों के लिए जीवन पर संकट खड़ा कर दिया है। इसके कारण जंगली जानवर लगातार बस्तियों की ओर रुख कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेंदुए के आबादी वाले इलाके में घुसने की कई घटनाएं सुर्खियों में आती रही हैं। इनके संरक्षण के लिए जंगलों की बेलगाम कटाई रोकनी होगी। प्राकृतिक आवास के लिए नए पार्कों का निर्माण करना होगा। इसके अलावा तेंदुए के जीवन पर संकट की वजह बनती रोडकिल की घटना की ओर भी ध्यान देना जरूरी है। इसके लिए सड़कों के विकास पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। देश में वन्य जीवों के खिलाफ लगातार बढ़ रही हिंसा की घटनाएं भी चिंतित करती हैं।

पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने के लिए वन्यजीव बेहद महत्वपूर्ण हैं। आज मानव जीवन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पारिस्थितिकी तंत्र पर टिका हुआ है। यदि पारिस्थितिकी में किसी भी प्रकार के असंतुलन की स्थिति पैदा होती है तो इसका सीधा असर मानव जीवन पर पड़ता है। वन्य जीव पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। लिहाजा प्रकृति के सौंदर्य को बनाए रखने के लिए वन्यजीवों का संरक्षण बेहद जरूरी है। यह वर्तमान समय की मांग है। हमें इस कथन की गंभीरता को समझने की आवश्यकता है कि किसी एक प्रजाति विशेष पर आने वाला संकट, न केवल उसके अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है, बल्कि अन्य प्रजातियों को भी मुश्किल में डाल सकता है। यह असंतुलन की स्थिति पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ कर रख देती है। लिहाजा वन्य जीवों का संरक्षण और संवर्धन बेहद जरूरी है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

एकतरफा चुनावी परिदृश्य

'कांग्रेस के लिए कठिन होती लड़ाई' शीर्षक से युक्त आलेख में संजय गुप्त का राजनीतिक विश्लेषण लगातार कमजोर होती कांग्रेस के लिए विचारणीय होना चाहिए। हिमाचल का घटनाक्रम कांग्रेस के मनोबल को तोड़ने वाला है। राज्यसभा चुनाव के दौरान पालाबदल की दूषित राजनीति से जहां हिमाचल में कांग्रेस स्वयं को बचा नहीं पाई वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सहयोगी बनी सपा भी इससे अछूती नहीं रही। इस आपाधापी के बीच कांग्रेस को हिमाचल में अपनी सरकार बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ा। इसके बाद भी पार्टी का अंदरूनी असंतोष पूरी तरह से खत्म हो गया है, इसमें संदेह बना हुआ है। मोदी विरोध पर टिकी राहुल की यात्राएं भी जनमानस पर अपना प्रभाव छोड़ पाने में कामयाब नहीं हो पाईं। उधर भाजपा ने आम चुनाव में बढ़त बनाने के उद्देश्य से 400 पार के बुलंद नारे के साथ 195 लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों की पहली सूची भी निर्गत कर दी, शेष प्रत्याशियों की दूसरी सूची के लिए मंथन जारी है। जबकि कांग्रेस अभी तक आइएनडीआइए में शामिल दलों के साथ अपनी मनोवांछित सीटों का गणित फिट करने में सफल नहीं हो पा रही है। 'मोदी हटाओ' के लक्ष्य को लेकर एकजुट होने वाले मोदी विरोधी राजनीतिक दल भी अपनी-अपनी महत्वाकांक्षा के चलते गठबंधन धर्म का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, इससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लोकतांत्रिक चुनावों में जो भी दल अपने प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए चुनावी मैदान में पहले उतर जाता है, उसे मतदाताओं के बीच अपना पक्ष रखने का भरपूर समय मिलता है। निःसंदेह भाजपा इस मामले में बढ़त पर है। पिछले दो कार्यकालों में आर्थिक घोटालों से मुक्त देश के चहुंमुखी विकास से प्रधानमंत्री मोदी के प्रति देश का विश्वास दृढ़ हुआ है। ऐसे में आम चुनाव का यह एकतरफा चुनावी परिदृश्य लोकतंत्र की दृष्टि से विमर्श का विषय बनने लगा है जिसमें देशहित की कसौटी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष को तौला जा रहा है।

pandeyvp1960@gmail.com

मेलबाक्स

जागरूक हों मतदाता

चुनाव आयोग ने आम चुनाव में राजनेताओं की बेजा बयानबाजी पर लगाम लगाने की पहल की है। उसने कहा है कि नेताओं की बेजा बयानबाजी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह अच्छा फैसला है, क्योंकि चुनाव के समय ऐसी बयानबाजी कुछ राजनेताओं की सुनने को मिलती है, जो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली होती है। हालांकि इसका कितना असर होगा कहना मुश्किल है। इसके लिए मतदाताओं को भी जागरूक होना पड़ेगा। हर किसी को बचपन में यह शिक्षा दी जाती है कि लालच एक बहुत बुरी चीज है, लेकिन इसका ज्ञान होते हुए भी कुछ लोग लालचवश गलत काम करने से भी नहीं चुकते, जो बाद में उनकी परेशानी का कारण बनता है। लोकसभा चुनाव में बहुत से राजनेता या फिर राजनीतिक पार्टियां कुछ लोगों को लालच देकर अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो लोग किसी लालच में आकर अपने मत का प्रयोग करते हैं उन्हें एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर वे कुछ पैसों की खातिर या फिर किसी उपहार के खातिर अपना मत देते हैं तो उनके ऐसा करने से सत्ता किसी गलत व्यक्ति के हाथों में जा सकती है। वह अपनी गलत नीतियों से आम जनता को परेशानी में डाल सकता है। जिस व्यक्ति ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए सौ रुपये खर्च किए होंगे वह सत्ता में आकर हजारों रुपये आम जनता से ही वसूलेगा। अपने मत का प्रयोग पूरी सावधानी से उसी तरह करना चाहिए जिस तरह हम सब बजार से कोई समान खरीदते समय करते हैं। इसी में ही आम जनता का कुछ भला हो सकता है। जब तक हम मतदान में सही उम्मीदवार चुनने के लिए रुचि नहीं दिखाएंगे तब तक देश की राजनीति में अच्छा बदलाव नहीं आएगा। और हम बहुत सी उन समस्याओं से जूझते रहेंगे जिनका हल करना सरकारों का कर्तव्य होता है। इसलिए पांच साल तक पछताने से अच्छा है, सभी चुनें और सही चुनें।

raju09023693142@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

अमर उजाला

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

नई दिल्ली ■ मंगलवार, 5 मार्च 2024

स्वच्छता को अपने आचरण में इस तरह अपना लें कि यह आदत बन जाए।
- महात्मा गांधी

शीर्ष अदालत ने झामुमो रिश्वत मामले में 25 साल पहले के निर्णय को सर्वसम्मति से पलटते हुए जो अभूतपूर्व फैसला सुनाया है, वह बेशक कानूनी नजीर है, लेकिन नैतिक नजीर तभी बनेगा, जब हमारे राजनेता इससे सबक लेते हुए एक स्वच्छ व पारदर्शी व्यवस्था बनाने की दिशा में आगे आएंगे।

जनप्रतिनिधि नजीर बनें

शीर्ष अदालत के सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) रिश्वत मामले में पांच न्यायाधीशों के 25 साल पहले के निर्णय को सर्वसम्मति से पलटते हुए जो फैसला सुनाया है, वह सही मायनों में अभूतपूर्व है। फैसले के अनुसार, रिश्वत लेकर सदन में भाषण या मत देने के मामलों में सांसदों/विधायकों को अभियोजन से कोई छूट नहीं मिलेगी और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। यह पूरा मामला दरअसल झामुमो के सांसदों से जुड़ा है, जिन पर आरोप था कि 1993 में जब तत्कालीन पीवी नरसिंह राव सरकार अविश्वास मत का सामना कर रही थी, तब इन सांसदों ने कथित तौर पर रिश्वत लेकर मतदान किया, और जब मामला सामने आया, तब अदालत ने यह कहकर उन्हें राहत दी कि सांसदों को सदन के भीतर दिए गए किसी भी भाषण और मतदान के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने के खिलाफ संविधान के तहत छूट प्राप्त है। शीर्ष अदालत इस मामले पर विचार कर ही रही थी, तभी यह मामला दोबारा तब उठा, जब झामुमो नेता शिबू सोरेन की बहू और विधायक सीता सोरेन ने अपने खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग की, जिन पर 2012 के राज्यसभा चुनावों में एक खास उम्मीदवार के पक्ष में मत देने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगा था। ये मामले संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) से जुड़े हैं, जिनका उद्देश्य महज यह सुनिश्चित करना है कि सांसद/विधायक सदन में बगैर किसी भय के अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम हों, लेकिन जनप्रतिनिधि अपने भ्रष्टाचार को ढकने के लिए इनका दुरुपयोग करते हैं। शीर्ष अदालत के फैसले का एक संदेश यह भी है कि जनप्रतिनिधि सदन के भीतर या बाहर जो बोलते हैं या जो कुछ करते हैं, उसे लेकर वे ज्यादा जिम्मेदार हों और उनका आचरण ऐसा हो, जो सर्वोच्च नैतिकता के आदर्श को बढ़ावा देने वाला हो। लोकतंत्र का प्रदूषण तभी रुकेगा, जब जनप्रतिनिधि इस दिशा में आगे

आएंगे। सवाल संसदीय लोकतंत्र में एक सांसद या विधायक की विश्वसनीयता का भी है। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उनके कुछ कर्तव्य होते हैं, जिनके निर्वहन में उनसे ईमानदारी की उम्मीद की जाती है। इस संदर्भ में प्रधान न्यायाधीश की यह टिप्पणी एक सबक की तरह है कि विधायिकाओं के सदस्यों द्वारा भ्रष्टाचार सार्वजनिक शुचिता को नष्ट कर देता है। अदालत का फैसला बेशक कानूनी नजीर है, लेकिन नैतिक नजीर तभी बनेगा, जब हमारे राजनेता इससे सबक लेते हुए एक स्वच्छ व पारदर्शी व्यवस्था बनाने की दिशा में आगे आएंगे।

आंकड़े दिशासूचक हैं

विभिन्न सर्वे बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था चमत्कारिक ढंग से आगे बढ़ रही है, जो अच्छी बात भी है। लेकिन आंकड़ों को दिशासूचक की तरह लेने की जरूरत है, क्योंकि सामने खड़ी चुनौतियां उन वास्तविकताओं की तरह हैं, जिन्हें हम नजर अंदाज नहीं कर सकते।

एक पुरानी कहावत है कि आमतौर पर लोग उस बात पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं, जिसे वे सच मानना चाहते हैं। हरेक कुछ महीनों में भारत की सार्वजनिक बहस में यही सच सामने आता है। अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में आंकड़े सामने आते ही बयानबाजी शुरू हो जाती है। बेहद ध्रुवीकृत राजनीतिक अखाड़े में समर्थक वाह-वाह करते हुए और शक्की अविश्वास में बहस करते हुए पाए जाते हैं। रह गए संशयवादी, तो वे संशय ही करते रहते हैं।

हाल ही में देश और दुनिया को बताया गया कि इस वर्ष अर्थव्यवस्था पांच जनवरी को पूर्वानुमानित 7.3 फीसदी नहीं, बल्कि 7.6 फीसदी की दर से विकास करेगी। उत्कृष्ट प्रदर्शन ने सबको हैरान कर दिया। दिसंबर, 2023 तक रिजर्व बैंक के पेशेवर पूर्वानुमान सर्वे ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए वास्तविक जीडीपी 6.0–6.9 फीसदी के दायरे में रहने की उच्चतम संभावना जताई थी। विकास दर में यह वृद्धि पिछले वर्षों और तिमाहियों के आंकड़ों में संशोधन के बाद हुई है, जिसके तहत वर्ष 2022–23 की जीडीपी विकास दर कम रही और मौजूदा वर्ष की पहली तिमाही के आंकड़ों में यह ऊपर दिखी। इसमें यह खुलासा भी किया गया कि अक्तूबर और दिसंबर, 2023 के बीच अर्थव्यवस्था 8.4 फीसदी की दर से बढ़ी। जीडीपी की 8.4 फीसदी दर पर बहुत ज्यादा उत्साह पैदा हुआ, जबकि इस अवधि के लिए सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) 6.5 फीसदी था। कम जीवीए को सब्सिडी पर कम खर्च और करों में वृद्धि के रूप में विश्लेषित किया जाता है। जीवीए में करों को जोड़कर और उसमें से सब्सिडी घटाने पर जीडीपी का आंकड़ा निकाला जाता है। दिलचस्प बात यह है कि तीन तिमाहियों में जीवीए क्रमिक रूप से 8.2 फीसदी से घटकर 6.5 फीसदी हो गया है।

शंकर अय्यर
वरिष्ठ पत्रकार

अर्थव्यवस्था की स्थिति पर बहसें अक्सर आंकड़ों की बारीकियों में खो जाती हैं। स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से ज्यादा और

पूर्वानुमानों से बेहतर प्रदर्शन किया है। यह बुनियादी संरचनाओं पर खर्च और जीएसटी एवं प्रत्यक्ष करों के आंकड़ों से भी स्पष्ट होता है। जीडीपी के अनुमान से विनिर्माण एवं निर्माण के क्षेत्र में भी मजबूत वृद्धि का पता चलता है। आय में वृद्धि और शेयर सूचकांकों की शानदार उछाल से इसकी पुष्टि होती है। यह सब स्वीकारते हुए भी कहना होगा कि सब कुछ ठीक नहीं है। ये अनुमान विकास की रफ्तार और गति में मंदी का भी संकेत देते हैं। वर्ष के अंत में 7.6 फीसदी का अनुमान बताता है कि चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर छह फीसदी के आस-पास होगी। सामाजिक व्यवस्था के अन्य तत्वों की तरह आर्थिक विकास भी औसत के नियम से नियंत्रित होता है। क्या यह गिरावट है, सांख्यिकीय प्रभाव है या कोई संरचनात्मक मुद्दा है, जिसे विकास को बनाए रखने के लिए संबोधित किया जाना चाहिए?

आंकड़े बताते हैं कि विकास की इस गति में हर क्षेत्र शामिल नहीं है। भले ही जीडीपी 7.6 फीसदी की दर से विकास कर रहा हो, पर तथ्य यह है कि निजी खपत मुश्किल से तीन फीसदी की दर से बढ़ रही है, जो चिंता का विषय होना चाहिए। खपत के आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि जीडीपी में खपत का योगदान 55.6 फीसदी होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि खपत में गिरावट एक मौसमी मुद्दा है या खर्च करने की क्षमता में बुनियादी गिरावट है। हालांकि पीड़ा को कम करने और खपत बढ़ाने के लिए सरकारी हस्तक्षेप किया गया है। लेकिन 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सेवा, 16 करोड़ से ज्यादा लोगों को ग्रामीण रोजगार के अलावा धन हस्तांतरण, घर एवं उपभोग्य सामग्रियों के प्रावधान जैसे कल्याणकारी कार्यक्रमों के आक्रामक विस्तार के बावजूद खपत घट रही है। इसका असर कम लागत वाली वस्तुओं की बिक्री एवं उपभोक्ता वस्तुओं तथा टिकाऊ निर्माताओं की कमाई पर दिख रहा है। दरअसल, अंतरिम बजट के पहले उद्योग मंडलों ने कल्याणकारी लाभों के विस्तार की बात की थी।

जीडीपी के अनुमानों में अन्य चिंताजनक आंकड़े भारत के दो सबसे बड़े नियोक्ताओं से संबंधित हैं। पहला सेवा क्षेत्र, जो बड़ी संख्या में नए रोजगार पैदा करता है और दूसरा कृषि, जो संपूर्ण कार्यबल के 45 फीसदी से ज्यादा कार्यबल को रोजगार देती है। कृषि में तीसरी तिमाही में संकुचन दिखाई दिया और वर्ष के अंत में उसकी वृद्धि दर 0.7 फीसदी हो सकती है। सेवा क्षेत्र भी पिछड़ गया है और दोहरे अंक की वृद्धि के ऐतिहासिक स्तर से काफी नीचे रुका हुआ है।

कुछ अन्य मुद्दों पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। देश की जनसांख्यिकी से पता चलता है कि युवा कार्यबल अब ज्यादातर उत्तर के सबसे आबादी वाले राज्यों में रहते हैं, जबकि विकास, रोजगार, आय और खपत का झुकाव भारत के दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों की ओर है। 60 हजार नौकरियों के लिए 48 लाख युवा आवेदन देते हैं, राज्यों में अक्सर पेपर लीक के मामले सामने आते हैं, इंजीनियरिंग एवं मैनेजमेंट कॉलेजों में कैंपस प्लेसमेंट में भारी गिरावट आई है। इन सबके मद्देनजर मूल्यांकन और सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है।

इसके अलावा, दुनिया भर के निगम जेनरेटिव एआई और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाले सिस्टम में करीब 200 अरब डॉलर का निवेश कर रहे हैं। वित्तीय क्षेत्र और आईटी सेवाएं भारत के शिक्षित युवाओं के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से हैं। वर्ष 2023 में दुनिया भर के बैंकों ने 60 हजार से ज्यादा नौकरियां खत्म कर दीं। पिछले हफ्ते नैसकॉम के चेयरमैन ने जेनरेटिव एआई द्वारा बीपीओ कर्मियों की जगह लेने के जोखिमों पर चिंता जताई। चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया के प्रमुख जेन्सेन हुआंग ने घोषणा की कि एआई कोडिंग को खत्म कर देगा। पश्चिम में प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाने से भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होता है।

आर्थिक विकास एवं नीति के लिए संदर्भ महत्वपूर्ण होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो हम जानते हैं और जो हम जानते हुए भी आंख मूंद कर बैठे हैं, के बीच झूल रही है। आंकड़ों को दिशासूचक की तरह लिया जाना चाहिए। आर्थिक विकास की गति, चुनौतियां, बाधाएं इत्यादि सब पर बहस होनी चाहिए। याद रखें, चुनौतियों का दबाव जितना ज्यादा होगा, अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उतना ही निखरता जाएगा।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

जोसेफ मर्फी

आप अपने अवचेतन मन की शक्ति के प्रयोग से जीवन में बहुत सारी ऊर्जा, पैसा, स्वास्थ्य और खुशहाली पा सकते हैं, बशर्ते आप इसका इस्तेमाल करना जानते हों। यह शक्ति आपके भीतर ही विद्यमान है।

मन की गहराई में छिपा है ज्ञान का भंडार

***आपके** अंतर्मन में असीमित भंडार छिपे हैं, यदि आप इस पर थोड़ा-सा भी ध्यान दें, तो आप इसे पा लेंगे और अपने आसपास की दुनिया को खूबसूरत बना लेंगे। यह एक तरह की सोने की खान है, जहां से आप जीवन को हर तरह से समृद्ध और आनंदमयी बनाने के लिए आवश्यक वस्तुओं को निकाल सकते हैं। अधिकतर लोग जीवन भर अज्ञानता में ही रह जाते हैं, क्योंकि वे अपने भीतर छिपे ज्ञान और प्रेम के असीमित भंडार के बारे में जान ही नहीं पाते। यहां से आप वह सब पा सकते हैं, जिसकी आप चाहत करते हैं। यह ठीक वैसे ही कार्य करता है, जैसे एक चुंबकीय स्टील का टुकड़ा, जो अपने भार से करीब बारह गुना तक भार उठाने की क्षमता रखता है, वहीं अगर इसकी चुंबकीय शक्ति न रहे, तो यह एक तिनके का भार भी नहीं उठा पाएगा। इसी तरह मनुष्य भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं चुंबकीय, आस्था और विश्वास से भरपूर। वे अपने प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं। वहीं दूसरे प्रकार के मनुष्य वे होते हैं, जिनका जीवन डर एवं शंकाओं से घिरा रहता है। इनके जीवन में कई अच्छे अवसर आते भी हैं, तब भी ये हमेशा इसी गफलत में रहते हैं कि अगर सफल न हो पाया तो क्या होगा? ऐसे लोग जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वे अपने डर के कारण प्रयास करने से भी कतराते हैं। वे जहां होते हैं, जीवन भर वहीं रह जाते हैं। ऐसे में सफल लोगों की श्रेणी में आने के लिए आपको भी एक प्राचीन रहस्य को जानना होगा।*

आपकी नजर में वह प्राचीन अद्भुत रहस्य क्या हो सकता है? क्या वह परमाणु ऊर्जा का रहस्य है? या मनुष्य का अंतरिक्ष में अन्य ग्रहों की यात्रा करने का रहस्य? या फिर दुनिया के विध्वंसक बम बनाने की कला का रहस्य है? नहीं, यह इनमें से कोई भी नहीं है। तो फिर वह सबसे प्राचीन अद्भुत रहस्य क्या है? आखिर उसे कहां खोजें? इसका उत्तर बहुत ही सरल है। यह रहस्य है आपके अवचेतन मन की अद्भुत और चमत्कारी शक्ति, जिस पर अक्सर मनुष्य सबसे कम ध्यान देता है। आप अपने अवचेतन मन की शक्ति के प्रयोग से जीवन में बहुत सारी ऊर्जा, पैसा, स्वास्थ्य और खुशहाली पा सकते हैं, बशर्ते आप इस छिपी शक्ति का इस्तेमाल करना जानते हों। यह शक्ति आपको कहीं खोजने जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह आपके भीतर ही विद्यमान है। आप इसे एक बार अच्छी तरह से समझ जाएंगे और इस्तेमाल करना सीख लेंगे, तो फिर जीवन के किसी भी पहलू पर इसका प्रयोग करना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। आपके अवचेतन मन की गहराई में असीमित ज्ञान, असीमित शक्ति और वह सब कुछ विद्यमान है, जिसकी आपको आवश्यकता है। जरूरत है, तो बस अवचेतन मन को समझने और विकसित करने की। इसके बाद आप देखिएगा, आप मन में जो चाहेंगे वह बाहरी जगत में भी साकार होने लगेगा।

अंतर्मन की दुनिया...

सूत्र

आंतरिक मन की दुनिया के विचार, भावना, शक्ति, प्रकार, प्रेम और सुंदरता को जानना आपका मूलभूत अधिकार है। हालांकि ये शक्तियां अदृश्य हैं, परंतु बहुत शक्तिशाली हैं। जब आप इन शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेते हैं, तो आप जीवन में खुशहाली, सुरक्षा और प्रभुत्व पाने के लिए आवश्यक शक्ति, ज्ञान पर भी अधिकार कर लेते हैं।

दूसरा पहलू

तहमीना दुर्रानी दरअसल साहित्य की दुनिया से ताल्लुक रखने वाली संभ्रांत महिला हैं, जो लाहौर में अपने फॉर्म हाउस में रहती हैं।

'शब्दों' और महंगी कारों की शौकीन एक बेगम

यह कहानी है पाकिस्तान के एक ऐसे कद्दावर नेता, जो पढ़ना-लिखना तक नहीं जानते, और उनकी बेगम की, जो इतनी संभ्रांत हैं कि अंग्रेजी में उपन्यास लिखती हैं और मर्सडीज गाड़ियों के संग्रह का शौक रखती हैं। यह नेता हैं पाकिस्तान के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ, जिनकी कम से कम एक मामले में अपने राजनीतिक विरोधी इमरान खान से समानता है। जैसे इमरान खान की तीसरी पत्नी बुशरा बीबी पर्दे के पीछे रहा करती हैं, वैसे ही शहबाज शरीफ अपनी दूसरी पत्नी और अंग्रेजी की मशहूर लेखिका तहमीना दुर्रानी के साथ कभी नजर नहीं आते। तहमीना दुर्रानी ने शहबाज से शादी करने से पहले दो बार शादियां की थीं। उन्होंने पहली शादी 17 साल की उम्र में अनीस खान से की थी, जो उनके स्कूली दिनों के दोस्त थे। फिर अनीस खान से तलाक के बाद उन्होंने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के असरदार नेता और जमींदार गुलाम मुस्तफा खार से निकाह किया। यह निकाह करीब चौदह साल चला। तहमीना ने खार के साथ बिताए दिनों पर एक उपन्यास *माई फ्यूडल लॉर्ड* भी लिखा, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी समाज के सामंतवादी चेहरे को तार-तार कर दिया।

विवेक शुक्ला

नवाबी ठाठ में पली-बढ़ी तहमीना दुर्रानी का जिंदगी को जीने का अंदाज किसी महारानी से कम नहीं। उनके पास करीब आधा दर्जन मर्सडीज और दूसरी महंगी कारें हैं।

तहमीना दुर्रानी ने अंग्रेजी में एक उपन्यास *माई फ्यूडल लॉर्ड* भी लिखा, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी समाज के सामंतवादी चेहरे को तार-तार कर दिया।

तहमीना दुर्रानी दरअसल साहित्य की दुनिया से ताल्लुक रखने वाली संभ्रांत महिला हैं। सवाल है कि तहमीना दुर्रानी जैसी पढ़ी-लिखी महिला ने शहबाज शरीफ जैसे शख्स को अपना जीवनसाथी कैसे बना लिया, जिनका पढ़ने-लिखने की दुनिया से दूर-दूर तक रिश्ता नहीं है। वह अंग्रेजी से भी कोई खास दोस्ताना नहीं रखते। दोनों का विवाह 2003 में दुबई में हुआ था। शहबाज शरीफ ने तहमीना दुर्रानी से पहले बेगम नुसरत से निकाह किया था। तहमीना के नाना नवाब सर लियाकत हयात खान बंटवारे से पहले पटियाला रियासत के प्रधानमंत्री थे। माना जाता है कि तहमीना को उनके पिता शाकीर उल्ला खान दुर्रानी भी बहुत कुछ देकर गए थे। दुर्रानी साहब बैंकर थे और पाकिस्तान की सेना में भी रहे।

जाहिर है कि नवाबी ठाठ में पली-बढ़ी तहमीना दुर्रानी का जिंदगी को जीने का अंदाज किसी महारानी से कम नहीं। फिलहाल वह शरीफ परिवार के पारिवारिक निवास 'जट्टी उमरा' में न रहकर, लाहौर में अपने फॉर्म हाउस में रहती हैं। उनके पास करीब आधा दर्जन मर्सडीज और दूसरी महंगी कारें हैं। अब शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो वह ज्यादातर इस्लामाबाद में ही रहेंगे। जाहिर है, उनका लाहौर आना-जाना काफी कम हो जाएगा।

आंकड़े

उपभोग खर्च में खाद्य हिस्सेदारी

हाल के दशकों में प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च में खाद्य की हिस्सेदारी घट रही है, जिसके चलते स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं।

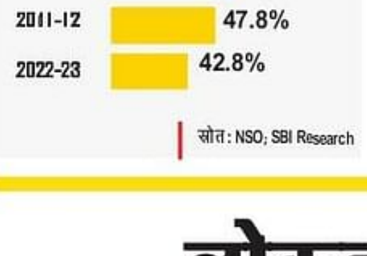

स्रोत: NSO; SBI Research

छल-कपटी और दुराचारी को भगवान कदापि सहन नहीं करते, जबकि निर्मल हृदय वाले सदाचारी भक्त भगवान की कृपा के स्वतः पात्र बन जाते हैं।

असहायों की सेवा

अंतर्यात्रा
शिवकुमार गोयल

परम विरक्त संत रामसुखदास जी कहा करते थे कि जो व्यक्ति मान-अपमान की भावना त्यागकर पूरी तरह से भगवान की शरण में चला जाता है, उसे किसी भी अभाव की अनुभूति नहीं हो सकती।

एक साधक ने स्वामी जी से प्रश्न किया, मैं रोजी-रोटी के साधन जुटाने में इतना व्यस्त रहता हूं कि भक्ति-उपासना नहीं कर पाता। मेरा कल्याण कैसे होगा?

स्वामी जी ने कहा, 'आप चार संकल्प लें- किसी का जी न दुखाएं, यथासंभव असहाय और रोगियों की सेवा करें, सत्य बोलें और सवेरे शैया त्यागने से पहले तथा रात्रि में सोते समय भगवान का स्मरण करें। कपट, चालाकी और छल से दूर रहें। भगवान स्वतः कृपा दृष्टि करेंगे।'

कुछ क्षण रुककर उन्होंने उस साधक को समझाते हुए कहा, वास्तव में भगवान ने सबको अपना मान रखा है, किंतु हम अपनी असीमित इच्छाओं के लालच में पड़कर झूठ, कपट आदि की शरण में चले जाते हैं और यह कहने लगते हैं कि बिना झूठ-कपट के सफलता नहीं मिलती है। वास्तव में हम सबका यह भ्रम ही हमारे पतन का कारण बन जाता है। छली-कपटी और दुराचारी व्यक्ति को भगवान कदापि सहन नहीं करते, जबकि निर्मल हृदय वाले सदाचारी भक्त भगवान की कृपा के स्वतः पात्र बन जाते हैं।

(अमर उजाला आर्काइव से)

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 14 अप्रैल, 1955

पुरानी रंजिश में समाजवादी कार्यकर्ता की हत्या

समाजवादी कार्यकर्ता की निर्मम हत्या

मुरादाबाद, १३ अप्रैल। यहां के पास दिलाटी में जिले प्रसिद्ध समाजवादी कार्यकर्ता श्री हरीशंकर, अपने पुत्र व पांच अन्य व्यक्तियों के साथ अपने खेत से वापिस आरहे थे कि मार्ग में उन पर दस व्यक्तियों ने लाठियों आदि से हमला कर दिया। ये लोग घात लगाये बैठे हुए थे, हरीशंकर व उनके दो साथी घटनास्थल पर ही मर

मुरादाबाद के दिलाटी गांव में समाजवादी कार्यकर्ता हरिशंकर, अपने पुत्र एवं पांच अन्य लोगों के साथ खेत से लौट रहे थे कि कुछ लोगों ने लाठियों से पीटकर उनकी हत्या कर दी। बताया जाता है कि पुरानी रंजिश के कारण यह हत्या हुई।

लोकतंत्र का विचार बदल रहा है

लोकतंत्र में सिर्फ संख्या के आधार पर व्यवस्था को रूप दिया जाता है। लेकिन नैतिक मूल्यों की आवश्यकता का केंद्र 'रामराज्य' में ही मिलता है।

वीर सिंह

मुद्दा

चुनाव की धुकड़-धुकड़ में सन्नाटा-सा छाया है! 'लोकतंत्र के पर्व' की दाल केवल चुनावी भट्ठी में ही गलती है! कृषि-प्रधानता छोड़, देश चुनाव-प्रधान हो गया है, इसलिए बारहों महीने रात-दिन चुनावी रणनीतियां बनती रहती हैं। देश किसी भी अभाव में चल सकता है, लोकतंत्र के बिना नहीं! मगर स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर विवादों और अलगाववाद के किले खड़े करते-करते लोकतंत्र स्वयं लड़खड़ाने लगा है और अपना जीवंत विकल्प मांगने लगा है। संयोग है कि इसी बीच राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भाजपा ने अयोध्या के राम मंदिर को देश के लिए 'ऐतिहासिक और अनुपम उपलब्धि' बताते हुए नए कालचक्र के श्रीगणेश के साथ भारत में अगले एक हजार वर्षों के लिए रामराज्य की स्थापना का एक संकल्प पारित किया है।

भारत की समृद्धि से भरी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धारा में शासन प्रबंधन के दो मॉडल प्रकट होते हैं : लोकतंत्र और रामराज्य। लोकतंत्र को

स्वतंत्रता और समानता के प्रकाश के रूप में पूजा गया है। दूसरी ओर, रामराज्य मूल रूप से भारतीय संस्कृति की सच्ची आत्मा को प्रतिष्ठित करता है तथा एक समरस और आदर्श शासन व्यवस्था प्रदान करता है। लोकतंत्र से जुड़े खतरों की गहरी पड़ताल करें, तो भारतीय संदर्भ में रामराज्य एक उपयुक्त और सार्थक विकल्प के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है।

लोकतंत्र वैश्विक रूप से अपनाए जाने वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं में से एक है, जिसे आदर्श शासन व्यवस्था माना जाता है और सैद्धांतिक रूप से यह आदर्श व्यवस्था है भी। लेकिन समय का पहिया घूमता है और किसी व्यवस्था में बाह्य तत्वों का शनैः शनैः अतिक्रमण उसे निर्मूल कर देता है। यही लोकतंत्र के साथ भी हुआ है और निरंतर हो रहा है।

स्वयं को लोकतंत्र का संरक्षक मानने वाले पश्चिमी और यूरोपीय देशों के लोकतंत्र में गैर-लोकतांत्रिक तत्वों का प्रदूषण इस हद तक फैल चुका है कि वह दिन दूर नहीं, जब इन देशों के मूल नागरिक इस पर पछताएंगे। भारत में लोकतंत्र-प्रदत्त स्वच्छंदता से भौगोलिक और सामाजिक-सांस्कृतिक विघटन की प्रक्रियाओं को ऑक्सीजन देने के लिए क्या जतन किए जा रहे हैं, इसका अनुमान कुछ राजनीतिक दलों, सामाजिक-मजहबी समूहों और व्यक्तियों के नित आने वाले वक्तव्यों से लगाया जा सकता है। भय, हिंसा, अशांति, अनैतिकता, भ्रष्टाचार, विषाक्त भाषा, धमकियां, अलगाववाद, देशद्रोह, और सामाजिक-सांस्कृतिक प्रदूषण सब लोकतंत्र की कोख में पलते हैं। लोकतंत्र में स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, अभिव्यक्ति, शोषण, अधिकार आदि सब पर्यायवाची-से बन गए हैं!

लोकतंत्र अब कोई पवित्र गाय नहीं रह गया है, जिसे प्यार से पाला-पोसा जाए और जिस पर गर्व किया जाए। इसके स्थान पर हम उस आदर्श शासन प्रणाली की ओर लौटें, जो सदियों से भारतीय मानस की रग-रग में जिंदा है और जिसकी कल्पना मात्र से ही हमारा रोम-रोम रोमांचित हो उठता है, जिसे हम रामराज्य कहते हैं। रामराज्य का अवतरण प्राचीन हिंदू शास्त्रों में होता है, विशेषकर *रामायण* में, जहां भगवान राम को न्यायपूर्ण और दयालु शासक के रूप में दिखाया जाता है, जिनके राज्य में सभी एक ही संस्कृति की छाया में रहते हैं, सब बराबर हैं, सब सुखी हैं, सब संपन्न, संतुष्ट और प्रफुल्लित हैं। रामराज्य धर्म, न्याय और करुणा के सिद्धांतों को अभिव्यक्त करता है। इसने समाज कल्याण को प्राथमिकता देने वाले दृष्टिकोण को विकसित किया है। नैतिकता और नैतिक शासन पर जोर देने से रामराज्य को भारतीय मूल्यों की अभिव्यक्ति के रूप में उठाया जाता है।

रामराज्य सामुदायिक कल्याण को सुनिश्चित करने पर जोर देता है। नीतियां और निर्णय सभी नागरिकों के कल्याण के प्रति दायित्व और समर्पण की भावना के आधार पर मार्गदर्शित होते हैं। शासन के जटिल परिदृश्य का सामना करते हुए, भारत स्वयं को जनतंत्र और रामराज्य के वादों और चुनौतियों के बीच फंसा पाता है। रामराज्य, जिसमें सामंजस्य, नैतिक नेतृत्व और सामुदायिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित है, एक प्रेरणादायक विकल्प के रूप में प्रकट होता है, जो भारतीय सभ्यता के मूल्यों का समर्थन करता है। जनतंत्रीय तत्वों और रामराज्य में समाहित शासन-गुणों के बीच संतुलन स्थापित करने से भारत जैसे विविध संस्कृति-संपन्न राष्ट्र के सामने आईं विशेष चुनौतियों का सामना करने का मार्ग खुल सकता है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 16

छतों पर बिजली

पिछले हफ्ते मंत्रिमंडल ने 75,021 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी। इस योजना में बिजली की पहुंच और देश की जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धता की पूरी गतिकी को बदल देने की क्षमता है।

इस योजना के तहत सरकार 1 किलोवॉट प्रणाली के लिए लागत के 60 फीसदी तक और 2 से 3 किलोवॉट प्रणाली के लिए अतिरिक्त लागत के 40 फीसदी तक की केंद्रीय सहायता प्रदान करेगी, यह सहायता की ऊपरी सीमा होगी।

करीब 1 करोड़ घरों को शामिल करने की संभावना वाली इस योजना के लाभार्थियों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। सरकार का कहना है कि मौजूदा कीमतों के आधार पर देखें तो 1 केवी प्रणाली के लिए 30,000 रुपये और 3 केवी प्रणाली के लिए 78,000 रुपये तक सब्सिडी बनती है।

एक कार्यान्वयन योजना से लैस, जिसमें एक तय राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करना और परियोजना को पूरा करने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की आठ इकाइयों को नियुक्त करना शामिल है, नई सूर्य घर योजना पिछली योजनाओं के मुकाबले बेहतर लग रही है। अगर सरकार ने सक्रियता से इनका समाधान नहीं किया तो पिछली योजना में जो मसले सामने आए वे इस बार भी असर डाल सकते हैं। यह कार्यक्रम मांग आधारित है, इसके लिए एक सरकारी पोर्टल पर आवदेन की जरूरत होगी, ऐसे में सवाल यह है कि सरकार जिस तरह के परिवारों को लक्षित कर रही है-ग्रामीण और/ या गरीब- क्या वे आवेदन करेंगे?

कई अक्षय ऊर्जा कंपनियों ने यह बात उठाई है कि राज्य जिस तरह से अपनी जनता को मुफ्त बिजली मुहैया करा रहे हैं, उसकी वजह से लोग रूफटॉप सौर प्रणाली को अपनाने से हिचकते रहे हैं। जब तक राज्य अपने बिजली सब्सिडी व्यवस्था की गहन समीक्षा नहीं करते, एक ऐसा कदम जो राजनीतिक वजहों से लंबे समय से सुधार से दूर रहा है, हालात में बदलाव नहीं आने वाला।

इसके अलावा सूर्य घर योजना के मुफ्त बिजली वाले हिस्से में यह माना गया है कि रूफटॉप सौर इकाइयां किसी ग्रिड से जुड़ी होंगी जो कि नेट मीटरिंग प्रणाली के जरिये घरों की अतिरिक्त बिजली खरीद लेगी। इसके कारगर होने के लिए दो मसलों का समाधान करने की जरूरत है। पहला यह है कि पहले से ही नकदी की तंगी से जूझ रही राज्यों की वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) सौर ऊर्जा को खरीदने के मामले में वित्तीय रूप से विवश ही रहेंगी। कई डिस्कॉम को नेट मीटरिंग प्रणाली से नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि पहले से ही उन्हें परिचालन पर निश्चित लागत को वहन करना पड़ रहा है और वे दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौतों (पीपीए) के तहत बिजली उत्पादकों को अनुबंधित शुल्क का भी भुगतान करती हैं।

कई को यह आशंका है कि उपभोक्ताओं को रूफटॉप सौर संयंत्रों से बिजली खरीद के लिए भुगतान करने से उनकी लागत बढ़ जाएगी, खासकर इसलिए कि इस बिजली को दिन के उजाले में हासिल करना होगा, जब टैरिफ आमतौर पर ज्यादा होता है। इससे कीमत निर्धारण की दूसरी समस्या पैदा होगी, जो कि इस वजह से जटिल है कि सौर ऊर्जा का टैरिफ लगातार घट रहा है, यह भी एक वजह है कि जिससे डिस्कॉम सौर ऊर्जा उत्पादकों के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहतीं।

ये अड़चनें इस बात की व्याख्या कर सकतीं है कि आखिर क्यों रूफटॉप सौर कार्यक्रम ने, जो कि दिसंबर 2015 से ही चल रहा है, योजना को प्रोत्साहन देने के लिए कई बार बदलाव किए जाने के बावजूद खराब प्रदर्शन किया है।

दिसंबर 2023 तक देश में रूफटॉप सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता सिर्फ 11.08 गीगावॉट की थी, जबकि लक्ष्य 40 गीगावॉट का था। इस क्षमता का करीब 80 फीसदी हिस्सा वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं का था। अभी देश में बहुत कम करीब 6,00,000 घरों ने ही रूफटॉप सौर प्रणाली को अपनाया है। तो जब तक सरकार बिजली वितरण कंपनियों की आपूर्ति और कीमत निर्धारण जैसी संरचनात्मक समस्याओं का समाधान नहीं करती, तब तक 1 करोड़ घरों तक इसे पहुंचाने का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा।

चुनाव पर मंडराता डीपफेक का खतरा

वर्ष 2024 के आम चुनाव के लिए डीपफेक एक बड़ा खतरा है और अगर इस पर अंकुश नहीं लगा तो 2024 चुनाव की प्रतिष्ठा पर आंच आ जाएगी। बता रहे हैं अजय कुमार

दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत आम चुनाव के लिए कमर कस रहा है। पिछले 75 वर्षों से भी अधिक अवधि में भारतीय चुनाव तंत्र ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। देश का यह तंत्र राज्य एवं केंद्र स्तर पर सरकारें स्थापित करता आया है। वर्तमान समय में कई चुनौतियां भी सामने आई है परंतु इनसे बेअसर भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने विभिन्न उपायों के जरिये- सचित्र मतदाता पहचान पत्र, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मतदान के तत्काल बाद मतदाता द्वारा सत्यापित किए जाने वाले विशिष्ट पत्र और चुनाव पर्यवेक्षक एवं चुनावी व्यय पर नजर रखने वाले तंत्र के जरिये अपना काम संजीदगी से किया है। मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए आयोग ने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया है।

2024 का आम चुनाव निर्वाचन आयोग के लिए एक और नई चुनौती लेकर आया है और वह है डीपफेक (भ्रमित करने वाले वीडियो एवं सामग्री) के कारण पैदा होने वाले खतरे। यह चुनौती साधारण नहीं है क्योंकि इसके कई घातक एवं दूरगामी नतीजे हो सकते है। इसका कारण यह है कि डीपफेक लोगों की निर्णय लेने की शक्ति प्रभावित करते हैं और मूल तथ्य एवं मनगढंत सामग्री के बीच अंतर समाप्त कर देते हैं। आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) के एक रूप जेनेरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स (जीएएन) की मदद से तेजी से डीपफेक प्रसारित किए जा सकते हैं। इस हथकंडे से चतुर लोग भी धोखा खा सकते हैं। उपयोगकर्ताओं के लिए इस्तेमाल में सहज जीएएन ऑनलाइन माध्यम में कुछ ही डॉलर में उपलब्ध है जिससे यह पूरा मामला और पेचीदा हो जाता है। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के डीपफेक भी आने लगे हैं जो इस बढ़ते खतरे की गंभीरता का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

हाल के वर्षों में सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कुछ लोग हथियार के रूप में कर रहे हैं। यहां पर भी शाब्दिक स्तर पर बदलाव या छेड़-छाड़ की हुई तस्वीरों के माध्यम से भ्रामक सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं। भ्रामक ऑडियो-वीडियो सामग्री से तथ्यों के साथ छेड़-छाड़ की आशंका और बढ़ जाती है। चुनाव के संदर्भ में बात करें तो डीपफेक चुनाव प्रक्रिया की प्रामाणिकता के लिए गंभीर चुनौती पेश करते हैं।

डीपफेक तैयार करने वाले लोग मतदान केंद्रों पर कब्जे की दुखद घटनाओं की याद दिलाते हैं। मगर डीपफेक बूथ पर कब्जा जमाने से भी अधिक खतरनाक हैं। ऐसे वीडियो तैयार करने वाले लोगों के पास कई हथकंडे होते हैं जिनमें विभिन्न मकसद के लिए संदर्भ आधारित फर्जी वीडियो भी शामिल हैं। इन वीडियो को खरीदने वाले लोगों में विदेशी शक्तियों से लेकर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी आदि शामिल होते हैं। डीपफेक का इस्तेमाल कर विदेशी शक्तियां चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालती हैं और चुनावी संप्रभुता को नुकसान पहुंचाती हैं। खासकर, वे देश ऐसा करने की ताक में लगे रहते हैं जो भारत को एक मजबूत सरकार चुनते हुए नहीं देखना चाहते हैं।

तकनीकी हस्तक्षेपों जैसे वॉटरमार्किंग, ब्लॉकचेन या क्रिप्टोग्राफी मतदाताओं की धारणा प्रभावित करने वाले डीपफेक पर अंकुश लगाने में कारगर नहीं होते हैं। भ्रामक खबरों का प्रसार अधिक होने की स्थिति में मानव की सोचने-समझने की क्षमता प्रभावित होती है जिसका असर यह होता है कि प्रामाणिक खबरों पर सनसनी पैदा करने वाली फर्जी सामग्री का दबदबा बढ़ जाता है। हालांकि, यह भी सच है कि डीपफेक का कोई पुख्ता इलाज नहीं है मगर तकनीक, नियमन एवं संचालन चुनावों पर इनके असर को कम कर सकता है। एक प्रभावी तरीका यह हो सकता है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली सामग्री पर लगातार नजर रखी जाए और जब भी कोई फर्जी खबर या सामग्री सामने आए उन्हें तत्काल समय रहते हटा दिया जाए। ऑडियो-वीडियो सामग्री में छेड़-छाड़ पकड़ने के लिए एआई तकनीक मौजूद हैं मगर असल चुनौती सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में प्रकाशित होने वाली सामग्री की वैधता की पहचान वास्तविक समय में करने की है। एक व्यावहारिक कदम यह हो सकता है कि ऐसी पोस्ट पर नजर रखी जाए जो असाधारण तेजी से अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रही हैं। निर्वाचन आयोग ऐसी संदेहास्पद पोस्ट की पहचान के लिए एक निश्चित सीमा तय कर सकता है। चुनाव से पहले इस रणनीति की पहचान के लिए आयोग अग्रणी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) की मदद ले सकता है। आयोग फर्जी सामग्री की जांच करने वाली तकनीक (फेककैचर टेक्नोलॉजी) उपयोग में लाने की संभावनाएं भी तलाश सकता है। यह तकनीक वास्तविक समय में फोटोप्लेथिमोग्राफी का इस्तेमाल कर भ्रामक एवं फर्जी वीडियो की पहचान कर सकता है।

डीपफेक के खिलाफ अभियान तेज करने के लिए, खासकर चुनावों के संदर्भ में, नियामकीय खामियों को दूर करना महत्त्वपूर्ण है। सूचना-प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम में अप्रैल 2023 में हुए संशोधन के अनुसार केंद्र सरकार सोशल मीडिया एवं मध्यस्थों को भ्रामक वीडियो या आपत्तिजनक सामग्री हटाने का निर्देश दे सकती है। निर्वाचन आयोग भ्रामक वीडियो की पहचान करता है और इन्हें केंद्र सरकार को इसे हटाने के लिए कहता है तो सरकार के लिए यह आग्रह मानना अनिवार्य है। मगर इसे लेकर कोई निश्चित समयसीमा नहीं होने से देरी होती है और इस दौरान सोशल मीडिया पर भ्रामक या आपत्तिजनक सामग्री का तेजी से प्रसार हो सकता है। एक ठोस कदम के रूप में सोशल मीडिया कंपनियों को आदेश देने का सीधा अधिकार निर्वाचन आयोग को देने के लिए आईटी नियमों में संशोधन किए जा सकते हैं। ये उपाय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव प्रक्रिया पर निगरानी, इस संबंध में आवश्यक निर्देश देने और पूरी प्रक्रिया पर नियंत्रण रखने के निर्वाचन आयोग के अधिकारों के अनुरूप बैठते हैं।

नियामकीय सुधार के अलावा भ्रामक एवं आपत्तिजनक सामग्री और वीडियो बनाने वालों के लिए जवाबदेही तय की जाना चाहिए। वर्तमान आईटी नियमों में ऐसी सामग्री हटाने का प्रावधान है मगर इन्हें बनाने वालों के लिए जुर्माने या दंड का प्रावधान नहीं है। भारतीय न्याय संहिता भ्रामक वीडियो बनाने वालों को उस स्थिति में जिम्मेदार मानता है जब उनकी गलत मंशा साबित हो जाती है। यानी यह सिद्ध करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष की बन जाती है। इन घटनाओं में तेजी और इनके दायरे को देखते हुए किसी व्यक्ति की मंशा साबित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लोगों को मूल सामग्री में बदलाव करने की सृजनात्मक एवं वैज्ञानिक आजादी दी जा सकती है मगर उन्हें ऐसी सामग्री में उनके द्वारा किए गए बदलाव की स्व-उद्घोषणा भी करनी चाहिए। इसका अनुपालन नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए। इससे भ्रामक वीडियो के प्रसार पर अंकुश लग सकता है।

इसके अलावा कानून में विदेश में बैठी इकाइयों द्वारा भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ भी कदम उठाने का प्रावधान होना चाहिए। चुनौती इसलिए भी बढ़ जाती है कि ज्यादातर डीपफेक गुप्त पहचान वाली इकाइयां विदेश से अपलोड करती हैं। इसे रोकने के लिए एक वैश्विक गठबंधन पर काम शुरू हो चुका है। मगर भारत की भू-राजनीतिक स्थिति को देखते हुए उन देशों से इस संबंध सहयोग की उम्मीद करना बेकार है जो ऐसी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। एक अधिक व्यावहारिक समाधान यह हो सकता है कि डीपफेक अपलोड करने, इनकी जांच में सहयोग और आपत्तिजनक सामग्री त्वरित हटाने के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग किया जा सकता है। एक अधिक कड़ा कदम यह हो सकता है कि आम चुनाव समाप्त होने तक जीएएन की उपलब्धता समाप्त कर दी जाए।

वर्ष 2024 के आम चुनाव के लिए डीपफेक एक बड़ा खतरा हैं। अगर इन्हें अपलोड करने से और इनका प्रसार नहीं रोका गया तो 2024 चुनाव पर डीपफेक का ठप्पा लग जाएगा। निर्वाचन आयोग के समक्ष कड़ी चुनौती है मगर इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इसके पास उन कई देशों के लिए मिसाल बनने का अवसर है जहां इस साल चुनाव होने जा रहे हैं।

(लेखक पूर्व रक्षा सचिव और आईआईटी कानपुर में अतिथि प्राध्यापक हैं)

बैजूस की विफलता के जाहिर थे संकेत

एडटेक कंपनी बैजूस कारोबारी दुनिया के सबसे उल्लेखनीय नाटकीय पतन के उदाहरणों में से एक की ओर बढ़ रही है। एक वर्ष से थोड़ा पहले भारत में पांच डेकाकॉर्न कंपनियां थीं। डेकाकॉर्न से तात्पर्य है ऐसी स्टार्टअप जिनका मूल्यांकन 10 अरब डॉलर के करीब हो। दुनिया में केवल 47 ऐसी स्टार्टअप हैं और सबसे मूल्यवान भारतीय स्टार्टअप थी बैजूस। वित्तवर्ष 21 में 4,588 करोड़ रुपये के घाटे के बावजूद 2022 के आरंभ में बैजूस का मूल्यांकन करीब 22 अरब डॉलर था। कंपनी अमेरिका में सार्वजनिक सूचीबद्धता वाली एक शेल कंपनी के साथ विलय करके अमेरिका में सूचीबद्ध होना चाहती थी।

शेल कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनियों से है जो सक्रिय न हों या जिनके पास कोई अहम परिसंपत्ति न हो। इसके लिए कंपनी 48 अरब डॉलर का मूल्यांकन रख रही थी। बैजूस के निजी इक्विटी निवेशकों के पास बहुत पैसा था और यह छद्म रूप से बढ़ा हुआ मूल्यांकन इसी की देन था। हाल ही में उनमें से कुछ निवेशकों ने एक असाधारण आम बैठक में बैजूस रवींद्रन को हटाकर नया बोर्ड गठित करने के लिए मतदान किया। रवींद्रन कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं। अगर इन निवेशकों को बैजूस का नियंत्रण हासिल भी हो गया तो भी यह ऋण मुक्ति से परे है। बैजूस रवींद्रन ने 2011 में थिंक ऐंड लर्न की स्थापना की थी। उन्हें 2013 में पहली फंडिंग हासिल हुई और 2015 में उन्होंने द लर्निंग ऐप लॉन्च किया जो हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल में केस अध्ययन के रूप में पेश हुआ। बैजूस ने 2017 में शाहरुख खान को अपना ब्रांड ऐंबेसडर बनाया। अगले सात वर्षों के दौरान कंपनी ने 29 दौर की फंडिंग के साथ अपना कारोबार 5 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया। उसने 2021 और 2022 में उसमें से 2.5 अरब डॉलर की राशि अधिग्रहण में व्यय कर दी। कंपनी 2019 में भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी की प्रायोजक बनी। कंपनी ने 2022 में लियोनेल मेसी को अपना वैश्विक ब्रांड ऐंबेसडर बनाया और कतर में आयोजित फीफा विश्व कप की आधिकारिक प्रायोजक बनी। कहा जा सकता है कि यह उसकी छद्म चमक-दमक का शिखर था। उल्लेखनीय बात यह है कि 2018 से ही निवेशकों ने कई चेतावनियों की या तो अनदेखी की या फिर वे उन्हें पकड़ने में चूक गए।

बैजूस के उत्पाद ग्राहकों को अपने स्तर पर आकर्षित नहीं कर पा रहे थे बल्कि आक्रामक बिक्री रणनीति का इस्तेमाल करके ऐसा किया जा रहा था। मुंबई के जाने माने चिकित्सक और अब एक ऐंजल निवेशक अनिरुद्ध मालपानी ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई थी। उन्होंने अपने ब्लॉग पर 50 से अधिक आलेख लिखे। उन्होंने 9 सितंबर, 2018 को पहला लेख लिखा था जिसके शीर्षक का हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह होगाः 'बैजूस पैसे कमाने की मशीन है। असल सवाल यह है कि क्या यह पैसे कमाने की मशीन बनेगी?' उनके आखिरी आलेख के शीर्षक का अनुवाद करें तो वह थाः 'बैजूस माता पिता को कैसे ठगती है?' इस आलेख में उन्होंने लिखा कि बैजूस ने अपने उत्पादों की बिक्री करने वालों से कहा कि वे मातापिता पर आरोप लगाकर, उन्हें शर्मिंदा करके येनकेन प्रकारेण अपने उत्पाद बेचें। उन्होंने स्कूलों और शिक्षकों की बुराई की और मां-बाप को यह चेतावनी तक दे डाली कि अगर उन्होंने बैजूस ऐप नहीं खरीदे तो उनके बच्चे प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाएंगे। उन्होंने ऐसे लोगों को कई साल की सबस्क्रिप्शन वाली योजनाओं में फंसा लिया। मालपानी के मुताबिक इसके लिए उन्हें रियायती दरों की पेशकश की गई, थर्ड पार्टी फाइनैंसर की मदद से मासिक किस्तों पर भुगतान की सुविधा दी गई और एक बार जब मातापिता ने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए तो वे इसमें उलझ गए और उनके बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। जो निवेशक अब बैजूस के संचालन और उसके मानकों को लेकर चिंतित हैं उन्हें उपरोक्त बातों पर भी ध्यान देना चाहिए था। इसके बजाय वे इस खराब तरह के कारोबार को बड़ा बनाने में मदद करते रहे। मालवानी ने लिंक्डइन पर भी बहुत कुछ लिखा और इसमें स्टार्टअप की पारिस्थितिकी से लेकर बैजूस की कार्य संस्कृति, कारोबारी मॉडल और उपभोक्ताओं के अनुभव आदि सभी शामिल हैं। जुलाई 2020 में मालपानी ने दावा किया कि उनका अकाउंट डिलीट कर दिया गया। बैजूस लिंक्डइन पर सबसे बड़े विज्ञापनदाताओं में से एक है। मालपानी के मुताबिक, 'बैजूस ने लिंक्डइन से शिकायत की और दावा किया कि मेरी पोस्ट अवमानना भरी हैं। जबकि कंपनी को पता था कि मेरी पोस्ट सही हैं। इसके बदले में लिंक्डइन ने स्थायी रूप से मेरा खाता ही बंद कर दिया। उन्होंने मुझे कुछ कहने का अवसर तक नहीं दिया।'

देवाशिष बसु

सभी मूल्यवान स्टार्टअप में एक साझा बात होती हैः वे लोगों से जुड़ी किसी गंभीर और बड़ी समस्या को हल करते हैं। उनका हल ऐसा होता है जो प्रभावी भी हो और लोगों को पसंद भी आए। बैजूस किसी समस्या को हल नहीं कर रही और उसका हल ऐसा नहीं है जिसे लोग पसंद करें। यह बात कोविड के समय साबित हो गई। बैजूस के लिए पैसे और मुनाफा कमाने का सबसे मुफीद वक्त वही था जब स्कूल बंद थे और बच्चों और शिक्षकों को एडटेक तरीके अपनाने पड़े। परंतु बैजूस ने वित्त वर्ष 21 और 22 में रिकॉर्ड घाटा होने की बात कही। दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आरोप लगाया कि बैजूस बच्चों के फोन नंबर 'चुरा' रही है और उन्हें अपने पाठ्यक्रम खरीदने के लिए धमका रही है। बैजूस ने इसका तगड़ा प्रतिवाद किया लेकिन बाद में उसने वादा किया कि वह बच्चों को अपने पाठ्यक्रम के साथ जोड़ते समय सकारात्मक सहमति लेगी और अपने कर्मचारियों को लोगों के घरों तक जाने से रोकेगी। उसके बाद कंपनी को उपभोक्ता अदालतों में मामलों में हार का सामना करना पड़ा और कई कर्मचारियों ने कंपनी के भारी भरकम लक्ष्यों और आक्रामक ढंग से कार्यक्रम बेचने की बात उजागर की है। बिना इन हथकंडों के बैजूस शायद इतना राजस्व नहीं जुटा पाती और घाटा और अधिक होता। सच यह है कि करीब 25,000 कर्मचारियों की छंटनी, कर्मचारियों की पीड़ा और उपभोक्ताओं की शिकायत आदि दिखाते हैं कि बैजूस के पास उपयोगी कारोबारी मॉडल नहीं है। बैजूस को धन मुहैया कराने वाले पीई फंड इस बुनियादी तथ्य को नहीं देख सके।

अप्रैल 2023 में प्रवर्तन निदेशालय ने बैजूस की मूल कंपनी थिंक ऐंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड तथा रवींद्रन के घर पर छापा मारा क्योंकि उसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन का शुबहा था। प्रवर्तन निदेशालय ने नवंबर 2023 में 9,362.35 करोड़ रुपये को लेकर कथित उल्लंघन के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया। उसी वर्ष जून में डेलॉयट हस्किंस ऐंड सेल्स ने यह कहकर काम बंद कर दिया कि कंपनी के वित्तीय वक्तव्य काफी समय से लंबित हैं। यह कंपनी 2016 से बैजूस का अंकेक्षण कर रही थी और 2025 तक उसे ऐसा करना था।

बैजूस हाउसिंग डॉटकॉम और जिलिंगो की राह पर जाती दिख रही है। यकीनन निवेशकों के हालिया कदम के बाद ऐसा होगा, जरूर बस समय लगेगा। जब भी नया प्रबंधन आएगा उसके पास चलाने के लिए उपयुक्त कारोबार ही नहीं होगा। घाटा बढ़ता जाएगा, बेहतर कर्मचारी साथ छोड़ जाएंगे और कंपनी को नकदी संकट से जूझना पड़ेगा।

(लेखक मनीलाइफडॉटइन के संपादक और मनीलाइफ फाउंडेशन में ट्रस्टी हैं)

आपका पक्ष

मोटापा स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन

विशेषज्ञों के अनुसार देश-दुनिया में मोटापा भी बहुत से लोगों की जान का दुश्मन बना या बन सकता है, क्योंकि मोटापा जानलेवा बीमारियों का एक कारण भी होता है। मोटापे के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर वर्ष 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है। आज हमने अपनी जीवनशैली और खानपान की आदतों को बिगाड़ कर अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। मोटापा भी कुदरत के विरुद्ध खानपान और जीवनशैली अपनाने से बढ़ता है।

लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और हमारे देश की सरकारें, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन बहुत से अभियान चलाते हैं। योग गुरु भी इसके लिए काम करते हैं, लेकिन हम उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और फिर गलत खानपान और जीवनशैली अपना कर अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं। कुछ लोगों ने अपने खानपान और जीवनशैली की आदत को बिगाड़ कर अपने स्वास्थ्य को खराब करने का काम तो किया ही है, साथ ही अपने बच्चों के स्वास्थ्य को भी दांव पर लगा रहे। मोटापा जानलेवा बीमारियों को न्यौता देता है। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2019-20 में किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) की पांचवीं रिपोर्ट का पहला भाग जारी किया, इसमें यह खुलासा हुआ है कि हमारे देश में बच्चों में कुपोषण और मोटापा बढ़ता जा रहा है। यह रिपोर्ट लगभग 22 राज्यों के सर्वेक्षण का जिक्र है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 20 राज्यों में 5 साल से कम बच्चों में तेजी से मोटापा बढ़ रहा है, इतनी छोटी उम्र में मोटापे के कारण महिलाओं का खुद के खानपान और बच्चों की सेहत की तरफ से गंभीरता से ध्यान न देना भी हो सकता है। आज हमलोगों को मोटापा को लेकर काफी सतर्क होना होगा, नहीं तो निश्चित रूप से इसके काफी दुष्परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। मोटापे को विभिन्न बीमारियों का कारण चिकित्सक कई वर्षों से बता रहे हैं मगर फिर भी हम लोग लगातार इसकी अनदेखी कर रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ही माना जाएगा। हमलोगों को मोटापे का कारण पहचानते हुए इसे दूर करने के उपाय तत्काल शुरू करने की जरूरत है, ताकि इससे बचा जा सके।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

अनुचित खानपान के कारण बढ़ता मोटापा लोगों के लिए खतरनाक है

एमएसपी पर सभी फसलों की खरीद करे सरकार

न्यूनतम समर्थन मूल्य तभी सार्थक है जब सरकार उस मूल्य पर सभी किसानों की सभी फसलें खरीदने की व्यवस्था करें। कई बार कम उत्पादन से समर्थन मूल्य से बहुत ज्यादा मूल्य पर फसलें बिक जाती है, तो कई बार कम मांग और अधिक उत्पादन के कारण भाव घट जाते हैं। समर्थन मूल्य पर सरकार उन्हें नहीं खरीदे तो समर्थन मूल्य का कोई मतलब नहीं है। यह बात कृषक भी जानते हैं कि सरकार सिर्फ गेहूं, धान और दलहन ही खरीदती है। अन्य फसलें बाजार में मांग के अनुरूप दामों में बिकती है।

सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

विदेश मंत्री एस जयशंकर और फ्रांस के यूरोप एवं विदेशी मामलों की सेक्रेटरी जनरल ऐनी मैरी डेस्कॉट्स ने सोमवार को नई दिल्ली में दोनों देशों से जुड़े मसलों पर चर्चा की।

पाक में फिर शहबाज

लगभग चार सप्ताह के इंतजार के बाद पाकिस्तान को शहबाज शरीफ के रूप में प्रधानमंत्री नसीब हुए हैं। प्रधानमंत्री के रूप में वह दूसरी बार सत्ता संभाल रहे हैं। जिन चुनौतियों के बीच वह पद से हटे थे, उससे भी ज्यादा चुनौतियों के बीच उन्होंने शासन की बागडोर हाथों में ली है। 72 वर्षीय शहबाज शरीफ करीब एक साल चार महीने देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जाहिर है, प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से हटाकर शहबाज प्रधानमंत्री बने थे और इसमें उन्हें फौजी जनरलों का साथ मिला था। अभी भी वह फौज की मदद से ही सत्तानशीं हुए हैं। हालांकि, उनके पक्ष में खूब चुनावी गड़बड़ियां की गई हैं और उनकी जीत असहज किस्म की है। भूला नहीं जा सकता कि किस तरह से विपक्ष की नारेबाजी के बीच शहबाज ने रविवार को नवनिर्वाचित संसद में बहुमत हासिल किया। पीएमएल-एन और पीपीपी के साझा उम्मीदवार शहबाज को 336 सदस्यीय संसद में 201 वोट मिले, वहीं जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के उमर अयूब खान को 92 वोट मिले हैं।

ज्यादातर जानकार मान रहे हैं कि नैतिक रूप से यह चुनाव इमरान खान ने जीता है और उनकी पार्टी के नेता-कार्यकर्ता सत्तारूढ़ गठजोड़ के नेताओं-कार्यकर्ताओं को देखते ही चोर-चोर के नारे लगा रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह चोर-चोर का नारा सत्ता पक्ष के साथ चिपक गया है और आने वाले समय में इस दाग से बचने के लिए शहबाज शरीफ को बड़े प्रयास करने होंगे। अगर वह काम के मोर्चे पर नाकाम रहते हैं, तो फिर चोर-चोर का जुमला उन्हें लगातार परेशान करता रहेगा। इस दौर में पाकिस्तान बड़ी मुसीबतों का सामना कर रहा है। वहां महंगाई दर 25 प्रतिशत के पार चल रही है। गलत नीतियों और विकास की उपेक्षा ने पाकिस्तान को आर्थिक संकट के गर्त में पहुंचा दिया है। कर्ज मांगकर किसी तरह से काम चलाया जा रहा है। चीन ने शहबाज शरीफ को बधाई दी है, मगर यह देखने वाली बात होगी कि क्या चीन अपने मित्र देश को आर्थिक संकट से उबार सकेगा? सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या शहबाज शरीफ दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ कमाल कर पाएंगे?

चोर-चोर का यह नारा पाकिस्तान में सत्ता पक्ष के साथ चिपक गया है और आने वाले समय में इस दाग से बचने के लिए शहबाज शरीफ को बड़े प्रयास करने होंगे।

शहबाज शरीफ से कितनी उम्मीद है? भारत के मद्देनजर अगर देखें, तो शहबाज ने प्रधानमंत्री चुने जाते ही कश्मीर का राग छेड़ दिया है, मतलब आतंकवाद के मोर्चे पर उन्होंने बिना देरी निराश किया है। पाकिस्तान के हुक्मरान की भारत विरोधी ग्रंथियां उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं हैं। इस्लामिक स्टेट और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) जैसे आतंकी संगठनों द्वारा पाकिस्तान पर हमले बढ़ गए हैं। साल 2023 में वहां खूब हमले हुए हैं, जिनमें लगभग 550 सुरक्षाकर्मियों और 400 नागरिकों की जान गई है। पाकिस्तान का शासन अपनी खोदी हुई खाइयों में ही देश को गिराए चला जा रहा है। दरअसल, पाकिस्तान का पूरा चुनाव फौज के साये तले हुआ है और फौजी जनरल ही देश का एजेंडा तय करते हैं, जिस पर वहां की चुनी हुई सरकार को चलना पड़ता है। शहबाज शरीफ में अगर काम करने की इच्छा होगी, तो वह सेना को मनाने की कोशिश करेंगे, मगर ऐसी ही कोशिश में इमरान खान का जो हश्र हुआ है, वह पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि जम्हूरियत के साथ मजाक है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अगर पाकिस्तान को अमन-चैन और तरक्की की राह पर ले जाएं, तो सबके लिए अच्छा है।

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले | 05 फरवरी, 1949

पाकिस्तान का बजट

जिस दिन भारत का आगामी वर्ष का बजट पेश किया गया, उसी दिन पाकिस्तान का भी सन् १९४९-५० का बजट वहां की असेंबली के सामने पेश किया गया। अर्थ-मन्त्री श्री गुलाम मोहम्मद ने इस बात पर सन्तोष प्रकट किया है कि आर्थिक और बजट के क्षेत्र में पाकिस्तान की स्थिति मजबूत है। विभाजन के बाद होने वाली घटनाओं के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई थी। ३१ मार्च १९४८ को समाप्त होने वाले वर्ष में उसे लगभग १० करोड़ का घाटा रहेगा। चालू वर्ष के लिए अनुमान लगाया गया है कि उसे ६३ लाख की बचत होगी। आगामी वर्ष सन् १९४९-५० के साल में १११ करोड़ २६ लाख आय और व्यय १११ करोड़ २० लाख अनुमानित किया गया है। आय-व्यय में रेल, डाक और तार का आय-व्यय भी शामिल है। इस प्रकार अगले वर्ष भी ६ लाख की बचत का अन्दाज लगाया गया है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और वह अपने लोगों की सुख-समृद्धि में वृद्धि कर सके तो यह इस देश के लोगों के लिए खुशी की ही बात होगी। एक पड़ोसी के नाते उसकी अच्छी-बुरी अवस्था का इस देश पर भी प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। पाकिस्तान भारत का कर्जदार है। इस देश ने अविभाजित भारत के कर्ज की सारी जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। पाकिस्तान सन् १९५२ से किस्तों में अपने हिस्से का कर्ज अदा करेगा। उसे ९ करोड़ रुपये तो सूद के तौर पर ही चुकाने पड़ेंगे। यदि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति मजबूत रही तो वह इस कर्जे की आसान अदायगी की आशा कर सकता है।

भारत की भांति पाकिस्तान भी सेना पर अपनी शक्ति से अधिक व्यय कर रहा है। भारत के अगले वर्ष के बजट में ३२२ करोड़ के कुल खर्च में रक्षा पर १५७ करोड़ अर्थात् करीब आधा व्यय करने का अनुमान किया गया है। इसकी तुलना में पाकिस्तान १११ करोड़ के कुल व्यय में से रक्षा पर ४७ करोड़ २२ लाख खर्च करने का अनुमान करता है। इसके अलावा पाकिस्तान के बजट में २७ करोड़ ३३ लाख रक्षा सम्बन्धी स्थायी कामों पर खर्च करने की गुंजाइश है। पाकिस्तान के अर्थ-मन्त्री ने इस सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच अच्छे सम्बन्ध कायम करने की अपील की है। दोनों देशों के बीच अच्छे सम्बन्ध रहें, यह सभी चाहते हैं।

संरक्षण हटते ही घुटने टेकते अपराधी

विभूति नारायण राय | पूर्व आईपीएस अधिकारी

पश्चिम बंगाल की राजनीति में अपराधियों का वर्चस्व हो गया है, ज्यादा चिंताजनक है कि देश के कुछ दूसरे हिस्सों में भी अपराधियों और राजनीतिक दलों के रिश्तों में कोई खटास नहीं दिखती है।

देश को संदेशखाली से क्या संदेश ग्रहण करना चाहिए? पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां के घर पर हमला कर उसके परिवारी जनों को अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर कर दिया। यही कार्रवाई इसका दायां हाथ माने जाने वाले सर्दार और शिबू हाजरा के साथ भी हुई। शेख शाहजहां के आतंक का तिलिस्म जितनी आसानी से टूट गया, उससे एक बात तो साबित हो गई कि सत्ता का संरक्षण हटते ही बड़े-बड़े फन्ने खां भी पानी मांगने लगते हैं।

संरक्षण के चलते ही कुछ दिन पहले इन्हीं गुंडों ने ईडी के अधिकारियों को न सिर्फ शेख शाहजहां के घर की तलाशी नहीं लेने दिया, बल्कि उनके साथ मारपीट भी की थी। पश्चिम बंगाल पुलिस पर आरोप लगा कि उन्होंने ईडी अधिकारियों की जगह इन गुंडों का ही साथ दिया था। अदालत में शेख की पेशी की छवियां कानून का सम्मान करने वाले किसी भी नागरिक को विचलित कर सकती हैं। वह पुलिस की टुकड़ी के बीच किसी राजनेता की तरह मुस्कराते और अपने समर्थकों का अभिवादन हाथ हिलाकर स्वीकार करते हुए न्यायाधीश के कमरे में प्रवेश कर रहा है। सत्ता दल का समर्थक होने के कारण शेख के साथ पुलिस का व्यवहार किसी आदरणीय को दिए जाने वाले सम्मान से लबरेज है।

शेख शाहजहां की राजनीतिक यात्रा में ही संदेशखाली का संदेश निहित है। यह व्यक्ति बांग्लादेश से संदेशखाली आया था और आपराधिक गतिविधियों के चलते उसे पुलिस से संरक्षण की जरूरत थी। इसके लिए वह सत्तारूढ़ दल सीपीएम में सक्रिय हुआ। सीपीएम के सत्ताच्युत होने के बाद स्वाभाविक ही था कि नए सत्ता दल तृणमूल कांग्रेस में चला गया। इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपराधियों और राजनीतिक दलों के बीच इसी तरह के रिश्ते बनते-बिगड़ते रहते हैं। ऐसे ही एक घटनाक्रम में 2007 के नंदीग्राम कांड के खलनायक तत्कालीन सत्तारूढ़ दल सीपीएम के तीन बार के सांसद और विधायक रहे लक्ष्मण सेठ ने बुरा वक्त आते ही उसे छोड़कर कांग्रेस, भाजपा और तृणमूल में आवाजाही करने में कोई संकोच नहीं किया। न ही किसी दल को इस आधार पर उससे कोई परेशानी महसूस हुई कि वह अपने क्षेत्र का कुख्यात बाहुबली रहा है।

संदेशखाली का यह संदेश संसदीय लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। यह इसलिए और भी चिंताजनक है कि यह पश्चिम बंगाल से आ रहा है। एक दौर था, जब कहा जाता था कि कोलकाता जो आज सोचता है, वह भारत के कल की सोच बनती है- 'व्हॉट कोलकाता थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमॉरो।' इस एक वाक्य में बंगाल की बौद्धिकता और रचनात्मकता के प्रति पूरे देश का सम्मान निहित था। 1970 के दशक से ऐसा क्या हुआ कि यही बंगाल आपराधिक राजनीति का केंद्र बन गया है? रूपांतरण की यह पूरी प्रक्रिया एक लंबे समाजशास्त्रीय अध्ययन का विषय हो सकती है, पर मैं यहां सिर्फ एक ऐसे कारक का उल्लेख करना चाहूंगा, जो अन्यथा तो जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करने वाला होना चाहिए था, पर पश्चिम बंगाल के मामले में ठीक उल्टा हुआ।

देश के दूसरे हिस्सों में सत्ता का विकेंद्रीकरण तीन स्तरों पर हुआ, पर यहां राजनीतिक कार्यकर्ताओं के रूप में सत्ता में भागीदारी के लिए एक चौथा तबका भी तैयार हो गया। शुरुआत वाम दलों से हुई, जिनकी ग्राम और मोहल्ला कमेटियां बनाई तो गई थीं सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और अधिकारियों पर नजर रखने के लिए, पर धीरे-धीरे वे भ्रष्टाचार और अपराध का केंद्र बन गईं। कुछ ही वर्षों में हालात ऐसे हो गए कि शहरों में मध्यवर्ग को अगर अपनी रिहाइश के लिए मकान बनवाना होता, तो मोहल्ला कमेटियों के लिए निर्माण की लागत का कुछ हिस्सा अलग रखना होता था। गांवों में भूमि विवादों का निपटारा वहां की कमेटियां करतीं, जो इसके लिए अपना हिस्सा वसूलतीं। शुरू में जरूर पार्टियों के ईमानदार कार्यकर्ता कमेटियों में लिए गए, पर जल्द ही तिकड़मबाज और बाहुबली इनमें भर गए और उन्हीं का वर्चस्व हो गया। सत्तारूढ़ मोर्चे के घटकों ने इनका इस्तेमाल मतदान बूथों पर कब्जे के लिए भी करना शुरू कर दिया। बंगाल में ही हमने बूथ कैप्चरिंग के सबसे जबर्दस्त प्रयोग देखे। ईवीएम आने के बाद भी स्थिति में बहुत फर्क नहीं आया। मोहल्ले और गांवों के जमीनी कार्यकर्ताओं की इनमें बड़ी भूमिका थी। शेख शाहजहां ऐसा ही एक जमीनी कार्यकर्ता है। संदेशखाली का संदेश यह भी है कि सत्ता जाते ही ये तथाकथित जमीनी कार्यकर्ता फौरन अपना रंग बदल देते हैं। संदेशखाली व सिंगुर जैसे इलाकों में सीपीएम की कमेटियां ही तृणमूल में चली गईं।

मुझे कोलकाता के अपने एक लेखक मित्र का अनुभव बड़ा दिलचस्प लगा। उन्होंने अपनी तीन दशकों की सरकारी नौकरी की बचत से एक मकान बनवाने का जब इरादा किया, तो वाम की सरकार थी। वह खुद एक प्रगतिशील लेखक थे, इसलिए उन्हें विश्वास था कि अपने परिचित वामपंथी नेताओं की मदद के चलते उन्हें स्थानीय कमेटी को 'टैक्स' नहीं देना पड़ेगा, पर थकाऊ भागदौड़ से निराश होकर उन्होंने प्रचलित परंपरा के अनुसार, अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा मोहल्ले के दादा को देना मान लिया। अभी उनका मकान आधा अधूरा ही था कि सरकार बदल गई। अगली बार जो लोग अपना हिस्सा वसूलने आए, वे पुराने चेहरे ही थे, पर इस बार उनकी मोटरसाइकिलों पर सीपीएम के नहीं, तृणमूल के झंडे लगे थे। इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि बीच-बीच में जब मीडिया राज्य में तृणमूल के कमजोर होने और भाजपा के मजबूत होने की खबरें चलाने लगता है, तो स्थानीय कमेटियों के बाहुबलियों के दलबदल की अफवाहें भी उड़ने लगती हैं। सत्ता से बाहर इनकी स्थिति पानी बिना मीन जैसी होती है।

निराशाजनक सिर्फ यह नहीं है कि बंगाल जैसे प्रांत की राजनीति में अपराधियों का वर्चस्व हो गया है, ज्यादा चिंताजनक है कि देश के दूसरे हिस्सों में भी अपराधियों और राजनीतिक दलों के रिश्तों में कोई खटास नहीं दिखती है। बिहार में हाल के सत्ता-परिवर्तन में बाहुबलियों की भूमिका छिपी नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुछ की समय पूर्व किसानों की भीड़ पर अपनी कार चढ़ा देने वाले एक मंत्री पुत्र की अदालत में पेशी के समय की छवियों को देखकर क्या आपको संदेशखाली के अभियुक्त शेख शाहजहां की आत्मविश्वास से भरपूर प्रफुल्लित छवि की याद नहीं आती? दोनों पुलिस और कानून को अपना चाकर मानते दिखते हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

लोकतंत्र को मजबूत बनाने में कारगर होगी एआई

जसप्रीत बिंद्रा | तकनीक विशेषज्ञ

पिछले करीब दो वर्षों से तकनीकी दुनिया की बहस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इससे होने वाले नफे-नुकसान के आस-पास सिमटी रही है। हालांकि, पिछले साल के उत्तरार्द्ध में इस विमर्श का रुख नकारात्मक हो गया, क्योंकि पूर्वाग्रह, कॉपीराइट, गोपनीयता और डीपफेक जैसे मुद्दे सामने आने लगे। अब जब दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तब 2024 वह साल साबित होने जा रहा है, जब एआई अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देगी, और वह यह है कि यह लोकतंत्र के हित में मददगार होगी या इसके विनाश में?

इस साल भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, इंडोनेशिया जैसे कई बड़े देशों में चुनाव होने वाले हैं। बेशक जेनरेटिव एआई से पहले डीपफेक मौजूद थे, पर अब 'सोरा' और 'स्टेबल डिफ्यूजन' जैसे उत्पाद अधिक लोकतांत्रिक बना दिए गए हैं, जिससे ये कहीं ज्यादा आसान, तेज और सस्ते हो गए हैं। इस साल की शुरुआत में बांग्लादेश व स्लोवाकिया में चुनाव हुए, और इन दोनों जगह डीपफेक एक अहम किरदार बनकर उभरा। बांग्लादेश में एक विपक्षी नेता को फलस्तीनियों के प्रति अपने समर्थन को लेकर असमंजस में देखा गया, जो वहां चुनावी जीत के लिए एक आत्मघाती कदम था। इसी तरह, स्लोवाकिया के चुनाव में एक प्रमुख दावेदार ने चुनावों में कथित धांधली की बात कही, और उससे भी अधिक चिंताजनक बात थी, बीयर की कीमत बढ़ाने का एलान, जो उनकी हार के कथित कारण बने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की फर्जी आवाज में लोगों से अमेरिकी प्राइमरीज में वोट न करने का आग्रह पहले ही किया जा चुका है, और 2016 का कैंब्रिज एनालिटिका विवाद तो कई लोग अब भी नहीं भूले होंगे। इन सबने 2024 के चुनावों को लेकर खतरे की घंटी बजा दी है।

डाटा विश्लेषण की इसकी उन्नत क्षमताएं चुनाव-संबंधी डाटा की निगरानी कर सकती हैं, जिससे धोखाधड़ी को पकड़ा जा सकता है।

हालांकि, मैं एआई को लेकर पूरी तरह आशान्वित हूं। यकीन न हो, तो पाकिस्तान का चुनाव देखिए। वहां एक पूर्व प्रधानमंत्री जेल में डाल दिए गए, उनकी पार्टी से चुनाव चिह्न छीन लिया गया और उनके उम्मीदवारों को डराया-धमकाया गया। बेशक, चुनाव नतीजों में अन्य पार्टियों की जीत की घोषणा की गई, लेकिन ज्यादातर रिपोर्टों में यही कहा गया कि भारी धांधली के बावजूद इमरान खान की पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। इमरान ने सलाखों के भीतर रहते हुए चुनाव प्रचार के लिए जेनरेटिव एआई का इस्तेमाल किया और एआई से लोकतंत्र के खत्म होने संबंधी तमाम दावों की हवा निकाल दी। मैं यहां किसी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन पाकिस्तान ने दिखाया है कि कैसे एआई का इस्तेमाल लोकतंत्र-विनाशक की भूमिका से इतर किया जा सकता है।

निस्संदेह, डीपफेक में विनाशक ताकत है और भारत व अन्य देशों के चुनावों में हवा बनाने या बिगाड़ने में इसका उपयोग किया जा सकता है। मगर एआई से चुनाव-सुधार की दिशा में काफी कुछ किया जा सकता है। पाकिस्तान का चुनाव तो सिर्फ एक पहलू है, एआई का इस्तेमाल चुनावों में पारदर्शिता व समावेशिता लाने और इसकी दक्षता बढ़ाने में किया जा सकता है। डाटा विश्लेषण की इसकी उन्नत क्षमताएं चुनाव-संबंधी डाटा की निगरानी कर सकती हैं, जिससे धोखाधड़ी को पकड़ा जा सकता है। यह मतदाता पंजीकरण या मत डालने से जुड़ी गड़बड़ियों का पता लगा सकती है। ईवीएम की सुरक्षा भी इससे बढ़ाई जा सकती है। घोषणापत्रों और प्रत्याशियों के बारे में स्थानीय बोली में, स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित सामग्रियां तैयार करके मतदाताओं को जागरूक किया जा सकता है। एआई की मदद से दिव्यांग मतदाताओं के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं, और मतदान केंद्रों पर लगने वाली बड़ी-बड़ी कतारें भी खत्म हो सकती हैं।

स्पष्ट है, एआई भी एक ऐसी तकनीक है, जो अत्यधिक विनाशकारी ताकत देती है, तो अप्रत्याशित लाभकारी क्षमता भी। हम जब डीपफेक की सहायता से चुनावों को प्रभावित करने संबंधी नापाक मंशा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तब हमें यह भी देखना चाहिए कि इस तकनीक से हमारे देश के लोकतंत्र को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है? इमरान खान की जीत से दुनिया भर में एआई की इस क्षमता का पता चलता है, फिर चाहे यह बेशक अभी अपूर्ण हो।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

आजादी के असली शत्रु

आंतरिक और बाहरी स्वतंत्रता को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। किसी भी देश से अधिक बड़ा है जीवन, और कोई भी देश सचमुच तभी स्वतंत्र है या हो सकता है, जब जीवन के मौलिक नियमों को पहचानकर वह अपने आप को उनके अनुकूल बना लेता है। इस नजरिये से देखें, तो आज कोई भी देश पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। हर जगह स्वतंत्रता बस कछ हद तक ही है।

स्वतंत्रता के असली शत्रु हैं : घिसा-पिटा जीवन, बेजान परंपराएं। संसार में भारत के समान शायद ही कोई दूसरा देश हो, जिसे परंपरा के हाथों ने इतना दबोच रखा हो। भारत की असली समस्या यही है। इसको हल कर लें, तो बाकी सब कुछ, जो भारत को पिछड़ा बनाए हुए है, सवेरे के कोहरे की तरह साफ हो जाएगा। जीवन के विधि-विधान को ठगा नहीं जा सकता। जिस जाति या देश ने अपने आंतरिक जीवन को मुक्त नहीं किया, उससे सच्ची स्वतंत्रता की आशा नहीं की जा सकती। भले ही वह बाहरी स्वतंत्रता सरीखी चीज पा ले, परंतु जब भी उस फल को चखा जाएगा, तो सारी चमक-दमक के बावजूद उसके अंदर धूल और राख ही मिलेगी।

भारत की महान आत्मा जंजीरों से जकड़ी हुई है। इसे मुक्त करें, तब यहां राष्ट्रों के बीच एक महान राष्ट्र का उदय होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि पुनर्जीवित भारत समूचे विश्व के पुनरुज्जीवन के लिए बहुत कुछ कर सकता है और वह करेगा भी। हमारी शानदार आध्यात्मिक विरासत है, परंतु एक चीज के न होने से यह बासी हो गई है, और वह है सच्चा स्नेह व दूसरों का ख्याल। आज हमारे अविस्मरणीय अतीत के प्रबल अवशेष क्या हैं? ये हैं घनीभूत क्रूरता व स्वार्थपरता, कम उम्र की बच्चियों की शादी, विधवाओं के विरुद्ध हृदयहीन प्रतिबंध, स्त्रियों से हमारा बरताव, जातिवादी ऊंच-नीच की प्रणाली। ये सारी बातें बताती हैं कि रूढ़ियों के मुर्दा बोझ ने हमारी उन सुंदर भावनाओं को कुचल दिया है, जो मानव जीवन को समरस बनाती हैं।

यह जात-पात क्या है? स्वार्थ की संगठित पद्धति है, यानी दूसरों से भिन्न समझने की इच्छा, पास में ऐसा कुछ होने का एहसास, जो दूसरों के पास नहीं है। ऐसी ही तमाम बातें हमें विरासत में मिली हैं, जिनके भार तले हम कराह रहे हैं।

भारत की आत्मा पर छाए सब बोझों को उतार फेंकें, तो आप पाएंगे एक गहरी अनासक्ति और यथार्थ का गहरा भाव, जो आज भी उतना ही प्रबल और जीवंत है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमारी संपूर्ण विरासत नहीं है, बल्कि यह उसका मुर्दा भाग है। इसके नीचे दबी पड़ी है भारत की सच्ची विरासत, उसका जीवंत भाग, अतीत का वास्तविक उत्तराधिकार। यह और कुछ नहीं, बल्कि मुक्ति की प्रतिभा, आजदी का जज्बा है और यह भारतीय प्रकृति के मूल में है। भारत की आत्मा पर छाए बोझों को उतार फेंकें, तो आप पाएंगे गहरी अनासक्ति और यथार्थ का गहरा भाव आज भी उतना ही जीवंत है।

जे कृष्णमूर्ति

धर्मेंद्र प्रधान | केंद्रीय शिक्षा मंत्री

एआई से लेकर सैटेलाइट ट्रैकिंग तक, तकनीक इस ग्रह की जैव-विविधता की रक्षा करने और उसे समझने में हमारी काफी मदद कर रही है। आइए, धरती के बहुमूल्य वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए इसकी शक्ति का लाभ उठाएं।

उम्मीदों से कहीं बढ़कर यह रफ्तार

वित्तीय वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर ने भारत सहित विश्व के समस्त आर्थिक विश्लेषकों को चौंका दिया है। इस दौरान भारत में सकल घरेलू उत्पाद में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि पहली तिमाही में वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 7.6 प्रतिशत थी। इन आंकड़ों को, विशेषकर उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में हुई तरक्की के आंकड़ों को देखकर यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि भारत आने वाले वर्षों में 10 प्रतिशत सालाना विकास दर हासिल करने की ओर बढ़ सकता है। इस वक्त हम विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन अगले कुछ वर्षों में हम नंबर तीन पर पहुंच सकते हैं। इसी तरह, भारतीय शेयर बाजार भी बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच रहा है, क्योंकि भारत में आर्थिक विकास की तेज रफ्तार को देखते हुए विदेशी निवेशक एवं विदेशी निवेश संस्थान, दोनों अपने निवेश को बढ़ाने जा रहे हैं।

तीसरी तिमाही में अनुमान से कहीं अधिक वृद्धि दर हासिल करने के पीछे दरअसल आर्थिक क्षेत्र के साथ-साथ सांस्कृतिक व आध्यात्मिक क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तन मुख्य भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। जैसे, भारत में विभिन्न त्योहारों को उत्साह के साथ मनाया जाता है और त्योहारी मौसम में लगभग हर परिवार ही कुछ न कुछ खर्च करता है। पिछले साल दीपावली त्योहार के दौरान लगभग चार लाख करोड़ रुपये की धनराशि भारतीय परिवारों ने खर्च की। इसी तरह, शादियों के मौसम में भी भारी-भरकम खर्च किया जाता है। अपने यहां अब धार्मिक पर्यटन में भी अपार वृद्धि देखने में आई है, क्योंकि इन क्षेत्रों की आधारभूत संरचना में आमूल-चूल सुधार हुआ है। इन धर्मस्थलों में पर्यटन के बढ़ने से न केवल रोजगार के तमाम नए अवसर निर्मित हो रहे हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी अपार बल मिल रहा है।

सरकार आर्थिक क्षेत्र में लगातार सुधार कर रही है और पूंजीगत खर्च में भी लगातार वृद्धि जारी है। इसका भी हमें व्यापक लाभ मिला है। इनके साथ-साथ अनौपचारिक क्षेत्र भी तेजी से औपचारिक क्षेत्र में बदल रहा है, जिससे कर संग्रहण के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी औपचारिक क्षेत्र में अधिक निर्मित हो रहे हैं। औपचारिक क्षेत्र पर ध्यान तो दिया ही जा रहा है। कुल मिलाकर, अब भारतीयों को आर्थिक क्षेत्र में लगातार अच्छे समाचार मिलने लगे हैं। इससे आने वाले दिनों के सुखद होने की उम्मीद बढ़ गई है।

प्रह्लाद सबनानी, पूर्व बैंककर्मी

अनुलोम-विलोम

जीडीपी वृद्धि दर

विशुद्ध रूप से आंकड़ों की बाजीगरी

चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान जीडीपी विकास के आंकड़े सामने आ गए हैं। एक बार फिर तथ्यों को घुमा-फिराकर पेश किया गया है और दावा किया गया है कि यह चमकते भारत का प्रतिबिंब है। मगर क्या वाकई ऐसा ही है? जीडीपी का मूल अर्थ है, सकल मूल्य वर्द्धन यानी जीवीए और सरकार द्वारा अर्जित करों का योग। सकल मूल्य वर्द्धन को ही अर्थशास्त्री वास्तविक आर्थिक गतिविधि आंकने का सर्वाधिक उपयुक्त मानक मानते हैं।

आंकड़ों के मुताबिक, इस दौरान जीवीए वृद्धि महज 6.5 प्रतिशत थी, लेकिन सरकार द्वारा अर्जित करों में 1.9 प्रतिशत का बदलाव हुआ है। इससे ऐसा लग रहा है कि जीडीपी ग्रोथ 8.4 प्रतिशत है। मगर सच यही है कि अधिक राजस्व संग्रह के कारण सरकार द्वारा अर्जित करों में वृद्धि नहीं हुई है- जो सही मायने में अच्छा ग्रोथ माना जाता है। आम आदमी को मिलने वाली सब्सिडी में कमी के कारण इसमें गिरावट आई है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है, व्यक्तिगत उपभोग व्यय, यानी वह पैसा, जो आम लोग वस्तु और सेवाओं के लिए खर्च करते हैं। वित्त वर्ष 2024 में निजी उपभोग के लिए खर्चे में वृद्धि अब तीन प्रतिशत होने की उम्मीद है, जो बीते 20 वर्षों में सबसे धीमी है।

कुल मिलाकर, ताजा आंकड़े आम आदमी के लिए गंभीर आर्थिक संकट के संकेत देते हैं। साल-दर-साल खपत मुश्किल से बढ़ रही है और सरकार से मिलने वाली सब्सिडी की मदद भी लगातार घटती जा रही है। जीडीपी ग्रोथ न तो बहुत आकर्षक है और न टिकाऊ। यह हमारी मध्यम अवधि के ग्रोथ के लिए खराब संकेत है। फिर भी, सत्तारूढ़ दल का पूरा प्रचार तंत्र इन आंकड़ों को प्रचारित-प्रसारित करने से बाज नहीं आ रहा, लेकिन हमें मौजूदा सरकार के आर्थिक प्रदर्शन से संबंधित इन दो प्रमुख तथ्यों को जरूर जान लेना चाहिए। पहला, जीडीपी के इन आंकड़ों के बाद भी, यूपीए की तुलना में एनडीए सरकार के कार्यकाल में ग्रोथ बहुत धीमा रहा है। यूपीए के शासनकाल में 7.5 प्रतिशत औसत वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर थी, जबकि मौजूदा निजाम में यह महज 5.8 प्रतिशत है। और दूसरा, राजग सरकार के दूसरे कार्यकाल में औसत जीडीपी वृद्धि दर तो 4.3 प्रतिशत है, जो 30 से अधिक वर्षों में सबसे कम है। जाहिर है, सच वह नहीं है, जो हमें दिखाया जा रहा है। इन आंकड़ों से भ्रमजाल फैलाने की भरसक कोशिश की जा रही है, जिससे हमें बचने की जरूरत है।

विक्रम स्वामी, टिप्पणीकार,

कानून सबके लिए समान

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले के जरिए देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को दिशा देने की कोशिश की है। इस बार मामला सांसदों को मुकदमा चलाए जाने से मिली संवैधानिक छूट का था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिए फैसले में इस छूट की सीमाएं रेखांकित करते हुए स्पष्ट किया कि कानून के शासन की राह में किसी तरह का अड़ंगा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने खींची सीमा

JMM घूस मामला | यह पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के कार्यकाल से जुड़ा एक मामला था, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों पर रिश्वत लेकर सरकार के पक्ष में वोट डालने का आरोप था। 1998 में इस मामले में दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यों की पीठ ने सांसदों पर मुकदमा चलाए जाने पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि उन्हें संविधान के तहत मुकदमे से छूट हासिल है। अब सात सदस्यों की संविधान पीठ ने इस फैसले को पलट दिया है।

कानून से ऊपर कोई नहीं | भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाय चंद्रचूड़ की अगुआई वाली संविधान पीठ का यह तर्क महत्वपूर्ण है कि सांसदों को जो छूट दी गई है, वह विधायिका के कामकाज के सुचारू संचालन से ही संबंधित है। उसे किसी भी सूरत में रिश्वत लेने की आड़ के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसा किया गया तो सांसदों और विधायकों की एक ऐसी बिरादरी बन जाएगी, जो कानून के ऊपर मानी जाने लगेगी।

फैसले की टाइमिंग | यह फैसला ऐसे समय आया है, जब देश में आम चुनाव की घोषणा होने वाली है। जाहिर है, ऐसे माहौल में इस फैसले का भी कुछ न कुछ चुनावी असर होने की संभावना नकारी नहीं जा सकती। दलगत समीकरणों से अलग हटकर कहा जा सकता है कि चाहे जिसे भी वोटों का जो भी नफा-नुकसान हो, इस तरह के फैसले अगर चुनावी मुद्दा बनते हैं तो आखिरकार राजनीति के शुद्धिकरण में मदद ही करेंगे।

नजरिया सीमित न हो | लेकिन यह मुद्दा स्वस्थ बहस की ओर ले जाए, इसके लिए जरूरी है कि इसे संकीर्ण नजरिये से न देखा जाए। सवाल यह है कि अगर पैसे का या तोहफों का लेनदेन रिश्वत है तो फिर मंत्री पद या चुनावी टिकट या किसी और चीज के प्रलोभन में दलबदल या क्रॉस वोटिंग करना और कराना क्या है? अगर इसे रिश्वत मानेंगे तो उसकी पहचान कैसे करेंगे? और फिर, इन कथित प्रलोभनों या पॉलिटिकल करियर में ऊंचाई हासिल करने की आकांक्षाओं से अलग राजनीति कैसे विकसित करेंगे?

तैयार जवाब नहीं | जाहिर है, इन कठिन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं हैं। लेकिन अगर राजनीति को स्वच्छ बनाना है तो इन सवालों से दो चार होना पड़ेगा।

धूप-छांव
दोस्ती का जज्बा

प्रणव प्रियदर्शी

परसेप्शन या धारणा बदलती रहती है। अब जब दुनिया ही निरंतर परिवर्तनशील है तो आसपास दिखते लोगों, घटनाओं, परिस्थितियों को लेकर बनी हमारी समझ कैसे चिरंतन हो सकती है? लेकिन परसेप्शन में बदलाव की जो जटिल प्रक्रिया है, वह अक्सर अजीबोगरीब हालात पैदा कर देती है। कभी दो शत्रुतापूर्ण विचारों वाले व्यक्तियों और प्रवृत्तियों को बेहद करीब ला देती है तो कभी मैत्रीपूर्ण विचारों को इस कदर खिलाफ कर देती है कि आदमी अकेलेपन की त्रासदी झेलता हुआ मर जाए।

ये सारी बातें तब एक जीते-जागते इंसान के रूप में साकार होकर सामने आ गईं जब उस दिन उनसे मुलाकात हुई। परिचय तो पुराना था, लेकिन ढंग से मिलना पहली बार हो रहा था। उन्होंने जब इस दुनिया में आंखें खोलीं तब आजादी के बाद का भारत बनना शुरू हुआ था। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू अपनी लोकप्रियता के शिखर पर थे। देश को बनाने की जो जद्दोजहद सरकार के जरिए हो सकती थी, उसकी अगुआई नेहरू ही कर रहे थे। लेकिन यह कथित जद्दोजहद समाज और देश की कुलांचे भरती आकांक्षाओं से मेल नहीं खा रही थी। उन जनाकांक्षाओं को अभिव्यक्ति मिल रही थी दो परस्परविरोधी विचारधाराओं की नुमाइंदगी करते दलों और नेताओं की बातों में। एक का नाता वामपंथी समाजवादी विचारों से था तो दूसरे का दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी विचारों से। सत्तर के दशक में जब पहली बार जनभावनाओं ने सत्ता की नकेल कसते हुए आपातकाल लाने वाली सरकार को उखाड़ फेंका, तब ये दोनों धाराएं एक साथ थीं। एक नौजवान के तौर पर हमारे ये मित्र भी उस जेपी आंदोलन का हिस्सा बने हुए थे। हालांकि वह थे समाजवादी धारा में शामिल, लेकिन आजादी के बाद से उस समय तक की सरकारों की कार्यप्रणाली को लेकर बनी उनकी समझ उस आंदोलन में शामिल दोनों धाराओं के लोगों की साझा समझ से ज्यादा अलग नहीं थी।

धीरे-धीरे वक्त ने करवट बदली और सत्ता में दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी धारा के लोग इस मजबूती से प्रतिष्ठित हुए कि लोकप्रियता का नेहरू जी का रेकॉर्ड टूटता दिखने लगा। इस पैराडाइम शिफ्ट ने उनके सभी पुराने समविचारी दोस्तों को दूसरी तरफ ला खड़ा किया। अब जब मौजूदा सत्ता नेहरू जी के कार्यों की कमियां याद दिलाती है तो उनके सारे दोस्त बौखला उठते हैं, पर ये अपने पुराने जज्बे पर कायम हैं। गलत समझे जाने और अपने सच के साथ अकेले पड़ने की पीड़ा आप उनकी आंखों में देख सकते हैं, मगर लोकतांत्रिक सहमति-असहमति भी तो कोई चीज होती है। जहां दोनों खेमे एक-दूसरे को भक्ति और छद्म प्रगतिशीलता का तमगा देते नहीं थकते, वहीं ये सज्जन हैं कि अपने पैसे ही विरोधी खेमे के एक मित्र के बेटे के रिसेप्शन अटेंड करने सैकड़ों मील दूर से अकेले चले आए कि जज्बा दोस्ती का भी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए।

बोल वचन
सर्र से निकली सुर्री

राहुल पाण्डेय

जैसे बचपन में बहुत से लोग साइकल चलाने की शुरुआत सीधे गद्दी पर सवार होने की जगह कैंची चलाकर करते हैं, वैसे ही लड़कपन में बहुत से लोग क्रिकेट में बैटिंग की शुरुआत टप्पे वाली बॉल की जगह सुर्री बॉल से करते हैं। सुर्री बॉल बाउंसर की तरह टप्पा खाकर सीधे गिल्ली उड़ाने के लिए नहीं आती, बल्कि बिना टप्पा खाए जमीन पर सरकते हुए आती है। इसे खेलना इतना आसान होता है कि इस बॉल पर जल्दी कोई आउट नहीं हो सकता। और जब कोई आउट हो जाता है तो हमेशा के लिए उसका यह कहकर मजाक उड़ाया जाता है कि अरे, ये तो सुर्री बॉल पर आउट हो जाते हैं। तो आज का शब्द सुर्री ही है, जिससे किसी चीज के सरकने का आभास होता है। मगर यहां भी एक पेच है। सुर्री सरकने से बना तो है, पर यह जरूरी नहीं कि यह हमेशा सरकता ही रहे। कभी हवा सरसराती है तो कभी बॉल। जब कानों के नीचे से हवा की एक पतली धार निकलती है, तो कहा जाता है सुर्री हवा थी। सर्दियों में ऐसी हवा खूब चलती है। हमने कितनी भी टोपी पहन रखी हो, कितने ही मफलर साट रखे हों, मगर सुर्री हवा कैसे भी करके कानों तक पहुंच ही जाती है। सुर्री एक पटाखा भी होता है, जो तार के जरिए या बिना तार के ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए सर्र जैसी आवाज निकालता है। इस पटाखे से पता चलता है कि सुर्री शब्द कोई आज का नहीं है, बल्कि मुगलों के जमाने में भी यह प्रयोग किया जाता था। मुगल आतिशबाजी के शौकीन थे, और उनके आतिशबाजी के बक्से में तरह-तरह की सुर्रियां रहती थीं। मोटी आवाज वाली सुर्री अलग तो पतली आवाज वाली सुर्री अलग। वैसे सुर्री पटाखे अंग्रेजों के यहां भी चलते हैं, सुर्री हवा भी खूब चलती है, और सुर्री बॉल भी। पर उनके पास इस शब्द के लिए इतने आसपास तो क्या, दूर-दूर तक कोई शब्द नहीं है। ऐसा लगता है कि सुर्री अंग्रेजी से भी सर्र से निकल गई।

AI Image

तालिबान राज में अफीम की खेती बढ़ी तो म्यांमार में सरकार-विद्रोही गुटों का ड्रग ट्रेड को मिला संरक्षण
सरहद पार से क्यों बढ़ा नशे का व्यापार

रंजीत कुमार

27 फरवरी को गुजरात के समुद्री तट से दो हजार करोड़ रुपये की 3300 किलो नशीली दवाएं पकड़ी गईं। ईरान के चाहबहार बंदरगाह से इसे एक नाव में लाया गया था। इस कार्रवाई में नौसेना के समुद्री टोही विमान P-8-I का भी इस्तेमाल किया गया। नशीली दवाओं का व्यापार करने वाले इतने ताकतवर हो गए हैं कि भारतीय नौसेना को ऐसे अभियानों में लगाना पड़ रहा है। असल में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार को भले ही तस्कर अंजाम दे रहे हों, इन्हें सरकारी तत्वों (सरकारी खुफिया एजेंसियों) की शह मिली हुई होती है।

भारत की चिंता | दोनों की सांठगांठ से नशीली दवाओं का धंधा भारत ही नहीं, लैटिन अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका तक को अपनी चपेट में ले चुका है। भारत इन नशीले पदार्थों का बड़ा व्यापारिक मार्ग और बाजार बना हुआ है। यही नहीं, इन नशीली दवाओं को रिफाइन करने में लगने वाले केमिकल का भारत से सप्लाई किया जाना भी सुरक्षा अधिकारियों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है।

आतंकी कनेक्शन | नशीली दवाओं के तस्कर स्थानीय अधिकारियों और नेताओं को अपनी गिरफ्त में लेकर अपना धंधा चमकाने में कामयाब होते हैं। आतंकवादी संगठन भी अपनी गतिविधियों के लिए जरूरी पैसा अक्सर नशीली दवाओं के कारोबार से हासिल करते हैं। अफगानिस्तान स्थित इस्लामिक स्टेट (खुरासान) के अलावा वहां के तालिबान शासकों और पाकिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान (TTP) की आय का एक बड़ा स्रोत मादक पदार्थ ही हैं।

गंदा है यह धंधा
- भारत बन गया है ड्रग ट्रेड का बड़ा बाजार
- ग्लोबल मार्केट के लिए भारत है ट्रांजिट रूट
- भारत सरकार को दिखानी होगी मुस्तैदी

पड़ोस में हैं गढ़ | वैसे तो ड्रग्स तस्करी के बड़े गिरोह लैटिन अमेरिका जैसे इलाकों में ज्यादा फल-फूल रहे हैं क्योंकि वहां सरकारों पर उनका दबदबा होता है। लेकिन भारत के पड़ोस में नशीली दवाओं के उत्पादन और व्यापार के दो बड़े गढ़ हैं, जिन्हें गोल्डन ट्राएंगल और गोल्डन क्रिसेंट के नाम से जाना जाता है। इन इलाकों से भेजी गई नशीली दवाएं अक्सर भारत के रास्ते दुनिया के बाजारों में पहुंचाई जाती हैं। गोल्डन ट्राएंगल में मुख्य तौर पर तीन देश हैं म्यांमार, लाओस और थाईलैंड जबकि गोल्डन क्रिसेंट में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान शामिल हैं।

अस्थिरता भी है कारण | वैसे तो ये इलाके पिछले कई दशकों से नशीली दवाओं के धंधे में शामिल हैं लेकिन देखा गया है कि जब भी इन इलाकों के देशों में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है, मादक दवाओं का धंधा तेजी पकड़ने लगता है। बेहिसाब कमाई वाले इस धंधे में अपराधी गिरोहों के साथ आतंकवादी तत्व भी शामिल होते हैं, जिनकी पीठ पर सरकारी खुफिया एजेंसियों का हाथ होता है।

AI Image

कमाई का जरिया | मिसाल के तौर पर, 2021 के बाद जब म्यांमार में फौज ने सत्ता हथियाई और अफगानिस्तान में तालिबान ने चुनी हुई सरकार को बेदखल किया, तब से नशीली दवाओं की फसलों का उत्पादन और धंधा तेजी से बढ़ा है। चूंकि इन देशों को अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से बाहर कर दिया जाता है, इसलिए यहां की सरकारें अपनी राष्ट्रीय आय के एक सुनिश्चित स्रोत के तौर पर अफीम की खेती को बढ़ावा देती हैं।

तीन गुना बढ़ी आय | संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, अफगानिस्तान में तालिबान के लौटने के बाद से अफीम की खेती 32 प्रतिशत बढ़कर 2,33,000 हेक्टेयर में होने लगी, जिससे उनकी आय तीन गुना बढ़कर 1.4 अरब डॉलर हो गई।

अफीम का धंधा | अफगानिस्तान को अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों से जो वित्तीय मदद मिलती थी, उसके रुकने के बाद तालिबान ने अफीम को अपने गैरकानूनी निर्यात का एक बड़ा स्रोत बना लिया है। अफगानिस्तान से विश्व बाजार को जो अफीम निर्यात होता है, उसमें उसका हिस्सा 80 प्रतिशत माना जाता है। इस अफीम को पाकिस्तान के रास्ते पंजाब भेजा जाता है, जहां से ट्रकों के जरिए पूरे भारत में पहुंचाया जाता है।

म्यांमार में बढ़ी खेती | इसी तरह म्यांमार से भी अफीम की खेती में भारी इजाफा होने की रिपोर्ट है। दिलचस्प है कि वहां फौजी शासकों को ही नहीं, कई विद्रोही गुटों को भी आय के एक प्रमुख स्रोत के रूप में अफीम की खेती का सहारा लेना पड़ता है। नशीली दवाओं के धंधेबाज अब क्रिप्टोकरंसी का भी इस्तेमाल करने लगे हैं।

अंडरवर्ल्ड नेटवर्क | भारत ड्रग्स कारोबार के इन दोनों बड़े केंद्रों के बीच फंस सा गया है। इन इलाकों के सबसे निकट भारत ही है जहां मादक दवाओं की खपत का विशाल बाजार ही नहीं, इसे रिफाइन करने की तकनीकी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, यह भी ध्यान देने की बात है कि नशीली दवाओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में अंडरवर्ल्ड नेटवर्क की बड़ी भूमिका होती है, जिसकी पुलिस और संबद्ध एजेंसियों में गहरी पैठ रहती है।

कुल व्यापार कहीं बड़ा | हालांकि नशीली दवाओं के धंधे पर रोक लगाने के लिए भारत में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जैसी संस्थाएं सक्रिय हैं और गुजरात के तट पर नशीली दवाओं की जो ताजा धरपकड़ हुई है, वैसी कामयाबी अक्सर मिलती है लेकिन इसे नशीली दवाओं की भारत में होने वाली कुल तस्करी का एक अंश मात्र ही माना जाता है।

युवाओं में बढ़ा चलन | नशीली दवाओं की आसानी से उपलब्धता का ही परिणाम है कि देश भर में युवा वर्ग में मादक दवाओं का चलन बढ़ता जा रहा है। इससे देश में सामाजिक तबाही तो फैलेगी ही देश की सुरक्षा पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। इसे राष्ट्रीय अभिशाप के तौर पर देखा जा रहा है जिससे लड़ने के लिए ईमानदार राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक मुस्तैदी की जरूरत है।

(लेखक अंतरराष्ट्रीय और राजनयिक मामलों के जानकार हैं)

गौरमेंट गिरना-गिराना आऊटडेटेड प्रॉब्लेम हुएला

तुम बोलताए कि 'लोकशाही कईसा चलेंगा?' अरे बाबा, मस्त चलताए। इत्ता बरस चलाए कि नईं? जो लोग लोकशाही का भीतर बईठेले, उसकूं फरक गिरताए क्या?

दीपक पाचपोर

अबी उस दिन का खबर पढ़के अपुन का भेजा टोटल सटकेला। अपुन बाबूराव को फोन करके बोला कि 'अपुन कूं तुमसे अर्जेंट में मिलना मांगताए।' बाबूराव कहेला कि 'घबरने का नईं। अबी अपुन उदर तुमारा पास आताए।' जबी घंटा-दो घंटा का बाद बाबूराव से अपुन मिला तबी अपुन उसकूं प्रॉब्लेम बताया बी नईं कि पैले वोईच कहताए। क्या कहताए, जरा सुन के लेने का!

बाबूराव- 'तुमकूं जबी अपुन पूछेंगा कि मुलुक का भीतर सबसे बड़ा प्रॉब्लेम कऊन सा होताए, अपुन जानताए कि तबी तुम खाली मुंडी खुजाता बईठेंगा, पन तुमकूं समज में नईं आएंगा कि कऊन सा प्रॉब्लेम बताने का। अपुन अईसा नईं बोलतए कि तुमकूं कंट्री का कोई जानकारी नईं होताए। तुम अक्खा दिन पेपर पढ़ेंगा, चैनल बदल-बदल के टीवी का समाचार देखताए। बचा बखत में तुम वाट्सएप, यूट्यूब देखके सीआईडी का माफिक अक्खा इंडिया का समाचार देख लेताए।'

बाबूराव नॉन-स्टॉप ट्रेन जईसा बोलताए- 'शॉर्ट में बोले तो तुमारा से कोई बी कुछ छुपाने कूं नईं सकताए। तुमारा पाकिट में बोले तो मुलुक का टोटल प्रॉब्लेम का फुल लिस्ट होएंगा। तबी बी अपुन तुमकूं पूछने का डेयरिंग काएंकू करताए। अपुन तुमारा जीके का चेकिंग नईं करताए, खाली इत्ताईच अपुन कूं समज के लेनेकाए कि तुम इदर-उदर का लफड़ा में जास्ती टाइम खोटी तो नईं करताए?'

खाली पीली

अपुन- 'अईसाए बाबूराव...' बाबूराव- 'अच्छा बाबा, तुमीच बताने का कि कंट्री का सबसे मेन कऊन सा प्रॉब्लेम होताए?' अबी तुम बोलेंगा कि महंगाई पे कंट्रोल करना मांगताए। पन बॉस, तुमकूं कोई पब्लिक का भीतर बोलताए क्या कि सब आईटम को सस्ता करने का? नईं न? बस, फिर गौरमेंट काएंकू अईसा करेंगा। फिर तुम कहेंगा कि पब्लिक का पास काम-धंधा नईं। काम-धंधा किसकूं मांगताए, भिड़ू? तुमारा गल्ली का लड़का लोग अक्खा दिन क्रिकेट खेलताए, पिक्चर देखताए, मोबाइल चलाताए। वो तुमकूं कबी बोला कि 'पप्पा, मेरे कूं काम करने का।'

अपुन बोला- 'पन बाबूराव, तुम अपुन कूं बोलने देंगा कि नईं...' बाबूराव- 'तुमकूं अपुन किदर रोकताए, ब्रादर? इदर लोकशाही होताए। सबकूं मचमच करने का फुलटू फ्रीडम होताए। तुमकूं जईसा लगताए न, वईसा बोलके लेने का! अपुन तुमारा टोटल प्रॉब्लेम सॉल्व करके देंगा। अपुन इत्ता बखत तक म्युनिसपेल्टी में काम कियेलाए। गटर सफाई से लेके रोड का जानवर पकड़ने वाला सब विभाग का काम कियेलाए। तुम खाली अपना प्रॉब्लेम बताने का।'

अपुन बोला- वो तुम उदर का आईटम देखेलाए क्या? वो गौरमेंट वाला दूसरा बाजू को वोट दियेलाए। अईसा कईसा चलेंगा, बाबूराव? सबकूं लोकशाही का नियम पालने का न? सब अईसा करेंगा कि कोई पार्टी का नाम पे पब्लिक का वोट लेंगा अऊर उदर मांडवली करके सदन का भीतर कोई दूसरा को वोट देंगा।

बाबूराव- 'भिड़ू, तुमारा खाली इत्ताईच प्रॉब्लेम है क्या? सच्ची बोले तो वो आऊटडेटेड प्रॉब्लेम हुएला। अपुन तुमकूं एक बात बताताए। ध्यान से सुन के लेने का! तुम बोलताए कि अईसा में 'लोकशाही कईसा चलेंगा?' अरे बाबा, मस्त चलताए। अबी तलक इत्ता बरस चलाए कि नईं? फिर, जो लोग लोकशाही का भीतर बईठेले, उसकूं कोई फरक गिरताए क्या? नईं न? तुम बी जास्ती फिकर नईं करने का! अबी अपुन तुमकूं तुमारा वाईफ, छोकरा-छोकरी का बात किएला न, वो इसी का वास्ते। अक्खा लोग जबी प्रॉब्लेम भूल गएले तबी तुम काएकू उसका बोम मारके टाइम खोटी करताए। खाली पीली टेंशन नईं लेने का! जित्ता टेंशन लेंगा, दिमाग का उत्ताईच दही जमेंगा। दूध से तुम दही बनाताए न, उसका चा बी बनताए। एक कड़क चा पियेंगा अऊर शिग्रेट का दो कश मारेंगा न, अक्खा प्रॉब्लेम धुंवा बनके हवा हो जाएंगा।' अपुन बी समज गयेला कि बाबूराव सही बोलताए।

शेयर करें अपने अनुभव
आम मुंबइया भाषा में यह लेख कैसा लगा हमें बताएं **nbtreader@timesgroup.com** पर, और सब्जेक्ट में लिखें-**'खाली पीली'**

हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, मगर लोगों को मोदी की गारंटी पर भरोसा है

लोकसभा चुनाव के लिए BJP ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव की तारीखों का भी एलान करेगा। हिमाचल प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव में BJP ने सभी चार सीटों पर जीत दर्ज की थी। उस वक्त राज्य में उसकी ही सरकार थी। अब समीकरण बदल गए हैं। राज्य में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में पूछा जा रहा है कि इन बदले समीकरणों का चुनाव में कितना असर होगा, क्या कांग्रेस का अग्निवीर मुद्दा उठाना BJP के लिए मुश्किलें पैदा करेगा और यह भी कि हाल में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की हार का क्या असर होगा। इन तमाम मसलों पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष **जयराम ठाकुर** से बात की **पूनम पाण्डे** ने। पेश हैं बातचीत के अहम अंश :

■ राज्य में लोकसभा चुनाव की क्या तैयारियां हैं? पिछले चुनाव में सारी सीटें BJP ने जीती थीं, लेकिन अब वहां कांग्रेस की सरकार है। इसका कितना असर होगा चुनाव में?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरे देश में लहर है। उनके विकास कार्यों से सभी को फायदा हुआ है। हर वर्ग के लिए PM ने काम किया है। देश लगातार प्रगति कर रहा है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश में बहुमत होने के बावजूद राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई, जो उसके लिए बहुत बड़ा झटका है। बजट पारित करने के लिए BJP के 15 विधायकों को सस्पेंड करना भी एक बड़ा मुद्दा है। राज्य में कांग्रेस सरकार की छवि खराब हुई है।

विशुद्ध राजनीति
इंटरव्यू

■ क्या मुद्दे हैं लोकसभा के? क्या स्थानीय मुद्दे भी आप उठा रहे हैं?

सबसे बड़ा फोकस तो प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग वोट देंगे। 10 सालों में जिस तरह से काम हुए हैं, उसे देखते हुए सभी को लगता है कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मोदी की गारंटी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। लोगों को मोदी के काम पर और उनकी गारंटी पर भरोसा है। राज्य में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन एक साल में ही उनकी असफलता सामने आ गई है। राज्य को नुकसान हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है और कांग्रेस किसी भी चीज को सही ढंग से हैंडल नहीं कर पा रही है। यह भी लोग देख रहे हैं और वोट देते वक्त इसके बारे में भी सोचेंगे।

■ कांग्रेस अग्निवीर का मुद्दा उठा रही है। हिमाचल प्रदेश में लगभग हर घर से फौज में कोई न कोई है। कितना असर होगा लोकसभा चुनाव में?

इस मसले को अब लोगों ने सही ढंग से समझ लिया है। शुरू-शुरू में कुछ लोगों ने कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की थी। लेकिन अग्निवीर को लेकर अब किसी को कोई दुविधा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में इससे कोई नुकसान नहीं होगा।

■ हिमाचल में राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान और उसके बाद जो हुआ, उसे कैसे देखते हैं ?

उसने कांग्रेस सरकार की असफलता को दिखाया। अभी कांग्रेस सरकार को आए हुए एक साल ही हुए हैं और उसकी नाकामी के कारण ही यह स्थिति आई। कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज हैं, विधायक नाराज हैं, मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, कैबिनेट मीटिंग से उठकर जा रहे हैं। हमने तो हालात को देखते हुए राज्यसभा कैंडिडेट खड़ा किया और उनके लोगों ने हमें वोट किया। हमारी जीत हुई। यह कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। बहुमत होने के बावजूद वे राज्यसभा चुनाव जीत नहीं पाए।

■ कांग्रेस की तरफ से आरोप लगे कि खरीद-फरोख्त हुई है?

इसका कोई मतलब नहीं है। यह कोई आज से नहीं था। आठ-नौ महीने से उनके नाराज विधायक सड़क से लेकर विधानसभा तक में बोले जा रहे थे। उनकी अपनी नाराजगी थी। कांग्रेस अपने लोगों को साथ नहीं रख पाई।

■ क्या नाराज लोग पहले से BJP के संपर्क में थे ?

स्वाभाविक रूप से जब कोई नाराज होता है तो कहीं न कहीं बात करता है।

■ आपकी क्या ऐसी तैयारी थी कि अगर सरकार गिरती है तो BJP सरकार बना सकती है?

हम राज्यसभा चुनाव को लेकर फोकस्ड थे। हम जीत भी गए। जब हमने देखा कि हाउस में इनका नंबर कम है तो हमने फाइनैंस बिल पर मत विभाजन मांगा, लेकिन मत विभाजन दिया नहीं। फाइनैंस बिल अगर विधानसभा में गिर जाता है तो सरकार चली जाती है। बजट पास करने के लिए इन्होंने BJP के 15 विधायकों को सस्पेंड किया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि बजट पास करने के लिए विपक्ष के विधायकों को सस्पेंड कर संख्या घटा दी जाए।

■ कांग्रेस के बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है। क्या लग रहा है कांग्रेस की सरकार बच गई?

हम इसे लीगल तौर पर एग्जामिन कर रहे हैं। स्पीकर ने इतनी जल्दी में फैसला दे दिया। उनका डिसक्वॉलिफिकेशन अनाउंस कर दिया, उसके बाद नोटिफाई कर वेकेंसी इलेक्शन कमिशन को भेज दी।

■ क्या राज्य से कुछ बड़े नाम BJP जॉइन कर सकते हैं?

वह तो देश भर में लोग कर ही रहे हैं। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत सारे लोग साथ आ रहे हैं। हर वर्ग से सपोर्ट हमें मिल रहा है। जो लोग पार्टी में नहीं हैं, वे भी पार्टी में आकर काम करना चाहते हैं। इतना जरूर है कि कोई BJP में आने की इच्छा जताता है तो पार्टी आकलन करती है कि कौन लोग लिए जा सकते हैं।

रीडर्स मेल
www.edit.nbt.in

■ समर्पित कार्यकर्ता ही ताकत

4 मार्च का संपादकीय 'कांग्रेस की मुश्किल' पढ़ा। देश के सभी राजनीतिक दलों की नजरें 2024 के आम चुनाव पर टिकी हैं। हालत यह है कि दशकों से कांग्रेस की बतौलत सत्ता सुख भोग चुके नेता भी उस डूबते जहाज को छोड़कर NDA में जाना चाह रहे हैं। BJP ने अपनी 154 उम्मीदवारों की सूची घोषित कर दी है। 6 मार्च तक बाकी की लिस्ट आने की संभावना है। इससे लगता है कि BJP कठोर परिश्रम से अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के अधिकतम प्रयास कर रही है। BJP की सबसे बड़ी ताकत उसके जमीनी कार्यकर्ता ही हैं। समर्पित कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी टीम किसी अन्य दल के पास नहीं है।

विभूति बुपक्या, ईमेल से

■ चुनाव लड़ने के लिए पैसा

यह पत्र 20 फरवरी को 'खाली-पीली' कॉलम में प्रकाशित लेख 'चुनाव का तिकिट लाने का पईसा चल के आएंगा' खाली पीली से संबंधित है। चुनाव का समय है। इस साल के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सभी दल अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। सत्ताधारी दलों की बात छोड़ दें, तो कुछ स्थानीय पार्टियां तो यह देखती हैं कि वह जिन्हें टिकट दे रही हैं, उनमें चुनाव लड़ने की क्षमता है भी या नहीं। लेकिन मार्केट का हाल ऐसा है कि टिकट मिलते ही प्रत्याशियों की पैसों की किल्लत खत्म हो जाती है। इसी को लेखक ने अपने व्यंग्य में हाइलाइट किया है।

कार्तिक सिंह, ईमेल से

■ पार्टी छोड़ने का कारण

पश्चिम बंगाल की राजनीति में खलबली मची हुई है। संदेशखाली हिंसा के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तापस रॉय ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। तापस रॉय के बीजेपी में जाने की अटकलें लग रही हैं। हालांकि कुछ दिन पहले भी उन्होंने पार्टी छोड़ने के संकेत दिए थे। उनका कहना है कि वे पार्टी और सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से तंग आ चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि वह पार्टी से निराश हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि इतने दिनों तक पार्टी से नाराजगी न दिखाने का कारण क्या हो सकता है?

सुमित रावत, ईमेल से

nbtedit@timesgroup.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

पाक में फिर शहबाज, अच्छे रिश्तों की बात छेड़ कश्मीर का मुद्दा उठाया – एक खबर
– कश्मीर का सपना पहले देखते हैं और रिश्ते की बात बाद में करते हैं!

माणिक मेहता

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
hindi.speakingtree.in

इतने इलाज के बाद भी हम बीमार क्यों होते जा रहे हैं

ओशो

न्यू यॉर्क के एक छोटे से स्कूल में जहां धनपतियों के बच्चे पढ़ते थे, एक बच्चे में कुछ अजीब से लक्षण दिखाई पड़ने लगे। चिंता की बात थी। कुछ पंद्रह-बीस दिनों से उस बच्चे ने हर चीज काले रंग में रंगनी शुरू कर दी थी। कोई भी चित्र बनाता तो काले रंग का बनाता। सूरज बनाता, गुलाब के फूल बनाता तो काले रंग का। समुद्र बनाता, मनुष्य बनाता तो काले रंग का। उसकी अध्यापिका चिंतित हो गई। काले रंग के प्रति उसका यह लगाव उसकी किसी निराशा और दुख के संकेत की खबर दे रही थी। उस बच्चे में अंधेरे के प्रति इतना मोह, काले के प्रति उसका इतना आकर्षण शुभ नहीं था। लिहाजा स्कूल के मनोवैज्ञानिक को इसकी खबर दी गई।

मनोवैज्ञानिक ने 15-20 दिनों तक खोजबीन की। बच्चे के घर में, पड़ोस में जाकर सारी जानकारी इकट्ठी की। उसके बाद एक बड़ी सी रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बड़े कारण बताए गए थे। बच्चे की घर की जिंदगी शायद सुखद नहीं थी। बच्चे के माता-पिता के बीच शायद अच्छे संबंध नहीं थे। झगड़ा था, विरोध था। घर का वातावरण उदास था। आसपास का वातावरण भी शायद अच्छा नहीं था। बच्चा जब गर्भ में था, तब उसकी मां बीमार रही थी। शायद इन सबका परिणाम बच्चे पर पड़ना शुरू हुआ। स्कूल के चिकित्सक को कहा गया तो उसने कहा शायद विटामिन्स की कमी है। उसकी वजह से बच्चा उदास और शिथिल हो गया। उसके जीवन में आनंद में कमी हो गई।

ये सारी रिपोर्टें आ गईं। उसका इलाज शुरू होता, उसके पहले एक और घटना घट गई और सारे निदान गलत हो गए। स्कूल के चपरासी ने स्कूल से निकलते वक्त बच्चे से पूछा, 'मेरे बेटे, मुझे तो बताओ, तुम काले रंग से ही चित्र क्यों बनाते हो?' उस बच्चे ने बताया कि सच बात तो यह है कि मेरी डिब्बी के सब रंग खो गए हैं और काला रंग ही बचा है। उसे दूसरे रंग दे दिए गए और दूसरे दिन से ही उसने काले रंग से चित्र बनाना बंद कर दिया। बात इतनी ही थी कि उसकी डिब्बी के बाकी रंग खो गए थे। लेकिन इन विशेषज्ञों ने बड़ी बातें खोज निकाली थीं। अगर उन बातों के आधार पर उस बच्चे का इलाज होता तो आप सोच सकते हैं, उस बच्चे का क्या हुआ होता। वे इलाज खतरनाक साबित होते, क्योंकि जो बीमारी ही न हो, उसका इलाज सिवाय खतरे के क्या हो सकता है।

मनुष्य के साथ भी बहुत तरह के इलाज किए गए। मनुष्य के सब इलाज खतरनाक सिद्ध हुए हैं। शायद हमने उसके भीतर जाकर पूछा ही नहीं। देखा नहीं कि असल बात क्या है? आदमी के भीतर की समस्या को ठीक से पकड़ने की कोशिश नहीं की और इलाज शुरू कर दिए। पांच-छह हजार वर्षों से मनुष्य के इलाज हो रहे हैं। सब तरह के विशेषज्ञ उसका इलाज कर रहे हैं। पर सचाई यह है कि मनुष्य ज्यादा से ज्यादा बीमार होता जा रहा है। सारे धर्मों के इलाज, सारे विशेषज्ञों, सारे गुरुओं, सारे पुरोहितों की चिकित्साएं मनुष्य को और मरणासन्न किए जा रही हैं।

मनुष्य पर ये इलाज जारी रहे तो शायद उसके और ज्यादा दिन बचने की संभावना ही न रहे। बहुत से निर्दोष और गरीब आदमी उनके बीच फंसे हैं। और शायद हम यह सीधा सा सवाल पूछना ही भूल गए हैं कि आदमी की सारी बीमारी, सारी बेचैनी, मन के स्वभाव से तो संबंधित नहीं है?

प्रस्तुति : दिलीप लाल

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्सः 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

कल्पमेधा

किसी भी आदमी को अपनी बुद्धि का बलिदान कर विनम्र बनने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज की पूजा तब तक नहीं की जानी चाहिए, जब तक तर्क को यह विश्वास न हो जाए कि वह पूजनीय है।
- वाल्तेयर

भ्रष्टाचार के विरुद्ध

यह विचित्र है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाने, उसके सफाए के लिए जंग का एलान करने वालों को खुद भ्रष्टाचार करने का एक तरह से हक हासिल था! अब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर कोई भी सांसद या विधायक रिश्वत लेकर सदन में सवाल पूछता या किसी पार्टी के पक्ष में मतदान करता है, तो उस पर भ्रष्टाचार का मामला बनता है। भ्रष्टाचार का मामला उस पर उसी समय बन जाता है, जब वह रिश्वत लेता है। दरअसल, अभी तक ऐसा करने वाले विधायक और सांसद ऐसे आरोपों में कानूनी कार्रवाई से इसलिए बच कर निकल जाते रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 105/194 में कहा गया है कि जनप्रतिनिधियों के सदन में कही गई किसी बात या किए गए किसी आचरण के खिलाफ अदालत में कार्रवाई नहीं हो सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यह अनुच्छेद पूरे सदन की सुरक्षा के मकसद से बनाया गया है, न कि किसी एक जनप्रतिनिधि की सुरक्षा के लिए। मामला दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक नेता से जुड़ा हुआ था, जिस पर आरोप था कि 2012 में उसने रिश्वत लेकर राज्यसभा चुनाव में दूसरे दल के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया था। इस मामले में नरसिम्हा राव बनाम भारत सरकार के मामले में आए फैसले की नजीर देते हुए आरोपी को बरी करने की गुहार लगाई गई थी। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने उस पुराने फैसले को भी अमान्य करार दे दिया।

नरसिम्हा राव मामले में कुछ सांसदों पर आरोप लगा था कि उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान के रिश्वत लेकर सत्तापक्ष के लिए मतदान किया। यह आरोप सीबीआइ जांच में सिद्ध भी हो गया था, मगर अदालत ने उसमें इसी तर्क से हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था कि सदन की कार्यवाही के दौरान सांसदों को सांविधानिक सुरक्षा प्राप्त होती है। मगर सर्वोच्च न्यायालय के ताजा फैसले से एक नई नजीर बनी है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह दलबदल कानून के भीतर से गली निकाल कर सरकारें गिराने और विधायकों के दूसरे दल की सरकार में शामिल हो जाने की घटनाएं बढ़ी हैं, रिश्वत लेकर राज्यसभा चुनाव में दूसरे दल के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान के मामले बढ़े हैं, उसमें सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला ऐतिहासिक माना जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह लाइन लांघ कर दूसरे दल के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का मामला आया, उसमें भी विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोप लग रहे हैं। संबंधित विधायकों के दलों ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तो की है, मगर इससे लोकतांत्रिक मूल्यों की शुचिता का भरोसा पैदा नहीं होता।

सांसद और विधायक आम लोगों के प्रतिनिधि होते हैं और जब वे रिश्वत लेकर सवाल पूछते या किसी दूसरे दल के समर्थन में उतर आते हैं, तो उससे वे सारे मतदाता छले जाते हैं, जिन्होंने बहुमत देकर उन्हें सदन में भेजा होता है। महाराष्ट्र, गोवा, बिहार और इससे पहले कर्नाटक, मध्यप्रदेश में चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया गया और वहां अल्पमत दलों की सरकारें बन गईं। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गहरी चोट पहुंची। सर्वोच्च अदालत ने भी कुछ मौकों पर इस प्रवृत्ति को घातक बताया था। अब ताजा फैसले से उम्मीद बनी है कि किसी भी प्रकार की रिश्वत लेकर अगर चुने हुए प्रतिनिधि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन करते हैं, तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो सकेगी। इससे शायद उनका मनोबल भी कुछ गिरेगा।

बेखौफ अपराधी

झारखंड के दुमका में एक विदेशी महिला से बलात्कार और मारपीट की घटना न सिर्फ अपराधियों के बेलगाम होते जाने, बल्कि कानून-व्यवस्था खोखला होने का सबूत है। इसमें आरोपियों ने जिस तरह पीड़ित महिला के खिलाफ यौन हिंसा की, उससे यही लगता है कि उस इलाके में पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं था। हालांकि जब मामला पुलिस के पास पहुंचा तो वह सतर्क हो गई और अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की बात कही जा रही है। मगर विडंबना है कि जब ऐसी कोई आपराधिक घटना हो जाती और जनआक्रोश उभरता तथा मामला तूल पकड़ लेता है, तभी सरकार और प्रशासन की नींद क्यों खुलती है। यही सक्रियता अगर सामान्य स्थितियों में भी कायम रहे, तो शायद किसी आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के भीतर कानूनी कार्रवाई का डर बन सकता है और इस तरह कई अपराधों को पहले ही रोका जा सकता है।

अफसोसनाक यह है कि भारत की 'अतिथि देवो भव' की परंपरा का गुणगान करते हुए दुनिया भर के लोगों से यहां आने का आग्रह किया जाता है। मगर विदेश से भारत घूमने आए पर्यटकों के साथ कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिन्हें उदाहरण मान कर खासतौर पर महिलाओं के लिहाज से यहां असुरक्षित और खतरनाक माहौल होने की बात कही जाती है। स्पेन की महिला के साथ जो हुआ, उससे एक बार फिर उसी धारणा की पुष्टि हुई है। सवाल है कि परदेस में भारत की ऐसी छवि न बने, इसके लिए यहां की सरकारें, पुलिस प्रशासन और आम लोग अपने स्तर से क्या करते हैं! आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से किसी विदेशी के भारत में आने और उसके साथ किए जाने वाले व्यवहार की अहमियत समझने की उम्मीद बेमानी है। यों किसी भी महिला के खिलाफ यौन हिंसा को लेकर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाने और उसे गंभीर अपराधों की श्रेणी में दर्ज किया जाना अनिवार्य होना चाहिए, मगर भारत में जिस 'अतिथि देवो भव' और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का हवाला दिया जाता रहा है, उसे सचमुच जमीन पर उतारना या सुनिश्चित करना सरकार और प्रशासन का ही दायित्व है।

बचपन पर मंडराता खतरा

अनेक जगहों पर अब भी छोटी बच्चियों को घरेलू सहायिका के रूप में काम पर रखा जाता है, तो छोटे बच्चों से दुकानों, खेतों और अन्य स्थानों पर काम कराया जाता है।

रोहित कौशिक

पिछले दिनों निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार में बच्चों और नाबालिगों को शामिल न करने के निर्देश दिए। आयोग ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि आम चुनाव में प्रचार के पर्चे बांटते हुए, पोस्टर चिपकाते हुए, नारे लगाते हुए या पार्टी के झंडे-बैनर लेकर चलते हुए बच्चे या नाबालिग नहीं दिखने चाहिए। आयोग ने कहा कि किसी भी तरीके से बच्चों को राजनीतिक अभियान में शामिल करना, जिसमें कविता पाठ करना, गीत, नारे या बच्चों द्वारा बोले गए शब्द या फिर उनके द्वारा किसी भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार के प्रतीक चिह्नों का प्रदर्शन करना दंडनीय होगा। अगर कोई भी दल अपने प्रचार में बच्चों को शामिल करता पाया गया, तो बालश्रम से संबंधित कानूनों के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रगतिशील दौर में भी बालश्रम के मुद्दे पर हम प्रायः मौन हैं। सवाल है कि क्या आजादी के अमृतकाल में हम बालश्रम के मुद्दे पर कोई ठोस पहल कर पाएंगे? यूनिसेफ की एक रपट के अनुसार भारत में हर दस श्रमिक में से एक श्रमिक बच्चा है। बालश्रम निवारण के लिए बने विभिन्न कानूनों के अतिरिक्त 2009 में बने 'शिक्षा का अधिकार' कानून के तहत भी बालश्रम को बढ़ावा देने वाले लोगों के खिलाफ दंड का प्रावधान है। 'शिक्षा का अधिकार' कानून के तहत बच्चों को अपनी शिक्षा पूरी करने का अधिकार दिया गया है, ताकि वे बालश्रम से दूर रह कर अपनी इच्छा के अनुसार भविष्य चुन सकें। इसके बावजूद ग्रामीण और शहरी इलाकों में बालश्रम को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। अनेक जगहों पर अब भी छोटी बच्चियों को घरेलू सहायिका के रूप में काम पर रखा जाता है, तो छोटे बच्चों से दुकानों, खेतों और अन्य स्थानों पर काम कराया जाता है।

एक रपट के अनुसार पूरे विश्व में 15.2 करोड़ बच्चे बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं, जिनमें से 7.3 फीसद बच्चे केवल भारत में बाल श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं। विडंबना यह है कि कोरोना काल ने बाल श्रमिकों को एक बड़े खतरे में डाल दिया है। संयुक्त राष्ट्र चाहता है कि शीघ्र ही पूरे विश्व में बालश्रम समाप्त हो जाए, लेकिन इस संबंध में मनुष्य के खोखले आदर्शवाद और संकुचित मानसिकता के कारण यह संभव नहीं लगता। कुल मिलाकर आज विभिन्न तौर-तरीकों से बचपन पर खतरा मंडरा रहा है।

बालश्रम के कारण आज अनेक बच्चे कुपोषण और विभिन्न बीमारियों से जूझ रहे हैं। अक्सर हम बालश्रम का अर्थ बहुत ही सीमित संदर्भ में लगाते हैं। जबकि अगर बच्चों के दिमाग पर किसी भी रूप में कोई दुष्प्रभाव पड़ रहा है और उनके दिमाग को परंपरागत श्रम से अलग श्रम करना पड़ रहा है, तो वह भी एक तरह का बालश्रम ही है। दुखद यह है कि हम इस परंपरागत बालश्रम पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन अपरंपरागत बालश्रम पर ध्यान नहीं देते हैं। कुछ वर्ष पहले 'सेंटर फार एडवोकेसी एंड रिसर्च' द्वारा जारी एक रपट में बताया गया था कि टीवी पर दिखाई जाने वाली हिंसा का भी बच्चों के दिलो-दिमाग पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। रपट में बताया गया था कि आज अनेक ऐसे बच्चे हैं, जो भूत और किसी अन्य भटकती आत्मा के भय से प्रताड़ना की जिंदगी जी रहे हैं।

'सेंटर फार एडवोकेसी एंड रिसर्च' ने बच्चों पर मीडिया के कुप्रभाव का व्यापक सर्वेक्षण कराया था। पांच शहरों में कराए गए इस सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष सामने आया था कि हिंसा और भय वाले कार्यक्रमों के कारण बच्चों के दिलो-दिमाग पर गहरा असर पड़ रहा है। शोधकर्ताओं का मानना है कि ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों पर गहरा भावनात्मक असर पड़ता है, जो आगे चलकर उनके भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस सर्वेक्षण में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पचहत्तर फीसद टीवी कार्यक्रम ऐसे हैं, जिनमें किसी न किसी तरह की हिंसा जरूर दिखाई जाती है। इन कार्यक्रमों से बच्चों पर गहरा मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक असर पड़ता है। रहस्य, रोमांच, भयावह कार्यक्रम और 'सोप ओपेरा' देखने वाले बच्चे जटिल मनोवैज्ञानिक समस्याओं से प्रभावित हो जाते हैं।

> **अक्सर हम बालश्रम का अर्थ बहुत ही सीमित संदर्भ में लगाते हैं। जबकि अगर बच्चों के दिमाग पर किसी भी रूप में कोई दुष्प्रभाव पड़ रहा है और उनके दिमाग को परंपरागत श्रम से अलग श्रम करना पड़ रहा है, तो वह भी एक तरह का बालश्रम ही है। दुखद यह है कि हम इस परंपरागत बालश्रम पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन अपरंपरागत बालश्रम पर ध्यान नहीं देते हैं। कुछ वर्ष पहले 'सेंटर फार एडवोकेसी एंड रिसर्च' द्वारा जारी एक रपट में बताया गया था कि टीवी पर दिखाई जाने वाली हिंसा का भी बच्चों के दिलो-दिमाग पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।**

इस समय भारत समेत दुनिया भर के बच्चों पर अनेक तरह के खतरे मंडरा रहे हैं। विडंबना यह है कि अब जलवायु परिवर्तन भी बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रपट के अनुसार दुनिया के 2.3 अरब बच्चों में से लगभग 69 करोड़ बच्चे जलवायु परिवर्तन के सबसे अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जिसके चलते उन्हें उच्च मृत्यु दर, गरीबी और बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 53 करोड़ बच्चे बाढ़ और उष्णकटिबंधीय तूफानों से सर्वाधिक प्रभावित देशों में रहते हैं। गौरतलब है कि इनमें से ज्यादातर देश एशिया में हैं। करीब 16 करोड़ बच्चे सूखे से गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में पल-बढ़ रहे हैं। इन क्षेत्रों में से ज्यादातर अफ्रीका में हैं।

एक अध्ययन में जलवायु परिवर्तन और बच्चों में कुपोषण के अंतर्संबंधों पर भी शोध हुआ है। पहले कुपोषण का अर्थ शरीर में पोषक तत्त्वों की कमी होना माना जाता था, लेकिन इस दौर में कुपोषण के अर्थ बदल गए हैं। अब ज्यादा या कम वजन होने का अर्थ भी कुपोषण ही है। यूनिसेफ की एक रपट के अनुसार दुनिया भर में करीब सत्तर करोड़ बच्चे कुपोषण की चपेट में हैं। यह जरूर है कि वैश्विक स्तर पर कुपोषित बच्चों की संख्या में पहले की अपेक्षा कमी आई है, लेकिन 'लांसेट' पत्रिका की एक रपट में जलवायु परिवर्तन के कारण भविष्य में कुपोषण की स्थिति और खतरनाक होने की संभावना व्यक्त की गई है। बीमारी के साथ-साथ ऐसे अनेक कारण हैं, जिनके चलते बीमार बच्चों का समय से ठीक होना संभव नहीं हो पाता। कई बार ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं भी ठीक ढंग से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। दूसरी तरफ, पिछड़े इलाकों में स्वच्छ पेयजल और साफ-सफाई का भी अभाव रहता है। जलवायु परिवर्तन इन्हीं सब कारकों को बढ़ा कर बच्चों के लिए अनेक समस्याएं पैदा करता है।

गौरतलब है कि आज की महानगरीय जीवन-शैली में माता और पिता दोनों ही अपने-अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, ऐसे में भी बच्चों की उचित और संपूर्ण देखभाल प्रभावित होती है। बहुत सारे परिवारों में बच्चों को आया या नौकर के सहारे छोड़ दिया जाता है। दरअसल, इस बदलते माहौल और गलाकाट प्रतिस्पर्धा के वातावरण में ढलने के लिए बच्चा जिस तरह से संघर्ष कर रहा है, वह भी बालश्रम ही है। बहरहाल, आज जरूरत इस बात की है कि हम बालश्रम के अर्थ को व्यापक रूप से ग्रहण करें। इस प्रगतिशील दौर में हम बालश्रम का पुराना अर्थ ही ग्रहण कर रहे हैं। बालश्रम के विभिन्न स्वरूपों पर बात करके ही हम सच्चे अर्थों में बचपन बचा सकते हैं।

खुशियों की चाबी

रेखा शाह आरबी

कहा जाता है कि हमारे चेहरे की मुस्कान हमारे चेहरे पर ईश्वर के हस्ताक्षर हैं। इसके बावजूद कुछ लोग अपने आप को जरूरी मौकों पर भी मुस्कुराने से रोकते हैं। खुश होने से रोकते हैं। दरअसल, उन्हें लगता है कि उनके जीवन में बेहद दुख है। मात्र कुछ भौतिक संसाधनों के अभाव के कारण उनको अपना जीवन कष्टकारी लगता है। ऐसी स्थिति में यह विचित्र लगता है कि लोग निर्जीव चीजों से सुख की अभिलाषा करने की कोशिश करते हैं। जब निर्जीव चीजों में कोई अपनी भावना होती ही नहीं है, तो वह किस प्रकार किसी के अंदर खुशियां भर सकती हैं। उसे देख कर और उसकी उपयोगिता के मद्देनजर उसकी सुविधा को लेकर थोड़ी देर के लिए राहत तो मिल सकती है, मगर सच्ची खुशी नहीं।

जबकि खुशियां तो एक तितली की तरह होती हैं, जिसके पीछे हम जितना भागते हैं, उतना ही वह आगे आगे उड़ती जाती है। अगर एक जगह हम रुक कर चुपचाप खड़े हो जाएं तो वह खुद हमारे कंधे पर आकर बैठ जाती है, क्योंकि खुशियां भौतिक संसाधनों से नहीं मिलती हैं। खुशियां धन-दौलत और ऐशो-आराम से नहीं मिलती हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, जो मानव मन के अंदर आंतरिक खुशी दे सके। सच यह है कि असली खुशी पाने के साधन ये नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनके पास इस तरह के भौतिक साधन और संसाधन उपलब्ध हैं। इसके बावजूद ऐसे लोग खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि खुशियां अंदरूनी होती हैं। बाहरी और बनावटी चीजों से खुशी हासिल नहीं की जा सकती।

खुशी अगर पानी है तो हमें अपनी सोच ऐसी बनानी होगी कि हम किसी भी हाल में रहें, प्रसन्न ही रहेंगे। ऐसी सोच बनते ही कोई भी दुख हमें ज्यादा देर परेशान नहीं कर पाएगा। ऐसे ही छोटे-छोटे कई उपाय हैं, जिनको करके हम सुखी हो सकते हैं। जीवन में हमें दुखी रहना है या खुश रहना है, इसका फैसला किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं करना होता है। आखिरकार यह हमें ही अपने अंतर्मन को बताना पड़ता है कि मुझे खुश रहना है, क्योंकि खुशियों का बाहरी व्यक्ति से कोई लेना-देना नहीं है। यह व्यक्ति को खुद तय करना होता है कि हम किस बात पर प्रसन्न होंगे और किस बात पर शोक मनाएंगे।

जब हम प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक हालत में अच्छाई ढूंढ़ने का प्रयास करने लगते हैं, तब वहीं से खुश रहना भी प्रारंभ कर देते हैं। मान लिया जाए कि हमें खुश रहना है तो सबसे पहले यह करना होगा कि अपनी थोड़ी भी आलोचना होने पर अपने आपको व्यथित करना बंद करना होगा। सबसे बेहतर तो यह होगा कि हम अपनी क्षमता में वृद्धि करें। जब हम हर एक छोटे कार्य में अपनी खुशी तलाशना प्रारंभ कर देते हैं तो खुश रहने के लिए बड़े-बड़े अवसर के मोहताज नहीं रह जाते हैं।

दरअसल, जीवन में बहुत खुशियों के बड़े अवसर बहुत कम बार आते हैं, लेकिन छोटे-छोटे अवसर प्रतिदिन आते रहते हैं। हर खुशी का एक मूल्य होता है। अगर हम खुशी के बहुत बड़े-बड़े अवसरों के पीछे भागेंगे तो उसका मूल्य भी हमें बड़ा ही चुकाना पड़ेगा। चाहे वह समय के रूप में ही क्यों न हो। हां, यह संभव है कि अगर हमें वह खुशी प्राप्त हो जाती है वह भी बड़ी ही होगी। एक व्यक्ति अपने परिवार को दुनिया भर के भौतिक संसाधनों के रूप में खुशियां देना चाहता है, जिसे कमाने के लिए अपने जीवन का बहुमूल्य समय अपने कामकाज को देना पड़ता है। जितने महंगे भौतिक संसाधनों की अपेक्षा, उतना ही बहुमूल्य समय का व्यय वहन करना पड़ता है। इसके अलावा, अपने आप को रचनात्मक कार्यों में लगाकर भी अपने आप को प्रसन्न रखा जा सकता है, क्योंकि जब हम कोई रचनात्मक कार्य करते हैं और किसी चीज का सृजन करते हैं तो उसका सृजन हमें आंतरिक खुशी से भर देता है। एक मूर्ति बनाता हुआ मूर्तिकार भी बेहद महत्त्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह सृजन कर रहा है।

हमारी खुशियों पर सबसे ज्यादा डाका तब पड़ता है, जब हमारी मानसिक शांति भंग होती है। हमारी मानसिक शांति तब अधिकतर भंग होती है, जब लोग हमारे साथ गलत व्यवहार कर देते हैं। अपनी गलती को चतुराई समझकर बात को स्वीकार भी नहीं करते हैं। इसके बाद उपजी स्थितियों में हम क्रोधाग्नि में जलने लगते हैं। ऐसे में अक्सर हम दूसरों के गलत किए की सजा खुद को देते हैं और दुखी रहने लगते हैं। अगर किसी ने गलत किया है और उसको वह स्वीकार नहीं करना चाहता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अपनी खुशियों को बरकरार रखने के लिए सबसे अच्छा है ऐसे लोगों को हम माफ करना सीखें और अपनी खुशियों को संभाल कर रखें। दूसरों के अपराधों की सजा खुद को आखिर क्यों दी जाए। अगर हम मन में मैल और दुर्भावना पाल रहे हैं तो यह अपने आप को ही सजा देने जैसा है। इससे उस व्यक्ति का कुछ भी बनना बिगड़ना नहीं है। जितनी भी नकारात्मकता पैदा होगी, वह हमारे अपने अंदर पैदा होगी और उसका नफा और नुकसान भी हम को ही भुगतान करना पड़ेगा। इसका सबसे सरल-सा उपाय है उस व्यक्ति को माफ किया जाए और अपने आप को अपनी प्रसन्नता के साथ प्रसन्न रखा जाए। जो इन सभी संसाधनों को अपनी खुशियों की चाबी बना लेता है उसे बाहरी दुनिया में प्रसन्नता और खुशियां ढूंढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि खुशियां उसके अंदर ही विराजमान है।

दुनिया मेरे आगे

> **अगर किसी ने गलत किया है और उसको वह स्वीकार नहीं करना चाहता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अपनी खुशियों को बरकरार रखने के लिए सबसे अच्छा है ऐसे लोगों को हम माफ करना सीखें और अपनी खुशियों को संभाल कर रखें। दूसरों के अपराधों की सजा खुद को आखिर क्यों दी जाए।**

आबादी की फिक्र

यह मानव अस्तित्व के लिए क्या संकट का समय है? एशिया के तीन औद्योगिक महाशक्ति चीन, जापान एवं दक्षिण कोरिया के घरों से बच्चों की किलकारियां लगातार गुम होती जा रही हैं। जापान एक कठिन जनसांख्यिकीय चुनौती का दौर से गुजर रहा है। इसका जन्मदर 2023 में लगातार आठवें वर्ष रिकार्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। जापान द्वारा 1899 में आंकड़ों का संकलन शुरू करने के बाद से जन्म की यह सबसे कम संख्या है। विवाहों की संख्या 5.9 फीसद गिरकर 489,281 जोड़ों पर आ गई, जो 90 वर्षों में पहली बार पांच लाख से नीचे है। अगर यही हाल रहा तो अगले कुछ वर्षों में ही जापान को वृद्धों का देश घोषित कर दिया जाएगा। सड़क-मोहल्लों से युवा शक्ति गायब मिलेगी, जिसका असर व्यापार और औद्योगिक इकाइयों में प्रतिकूल पड़ेगा। जो जापान कुछ हफ्तों पहले तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश हुआ करता था, वह चौथे स्थान पर खिसक गया है। आने वाले वक्त में उसकी आर्थिक स्थिति और कैसी होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है।

- जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर

नशे के खिलाफ

हाल ही में नारकोटिक्स ब्यूरो को एक संयुक्त अभियान में तीन हजार किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त करने में सफलता मिली। निश्चित रूप से यह आबकारी ब्यूरो की बहुत बड़ी कामयाबी है। हालांकि नशीले पदार्थों की तस्करी का यह पहला मामला नहीं है और जब तब ऐसे समाचार प्रकाश में आते रहते हैं। इसके बावजूद उम्मीद जगती है कि भविष्य में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए कड़े और ठोस कदम उठाए जाएंगे। मादक पदार्थ कौन ला रहा है, यह तो संबंधित महकमे ने पता लगा लिया, लेकिन यह मालूम करना भी जरूरी है कि इन्हें कौन मंगवा रहा है, कौन भेज रहा है और कहां खपाया जा रहा है। इन मूल प्रश्नों का उत्तर खोजे बिना तस्करी पर पूरी तरह लगाम लगाना मुश्किल है। इसलिए नशे के इस घृणित कारोबार की जड़ों पर प्रहार करना और इसे समूल नष्ट करना सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए, अन्यथा गुजरात को भी नशे के कारोबार में डूबने में देर नहीं लगेगी। इसके साथ ही नशा तस्करी की पिछली वारदातों की जांच पड़ताल के निष्कर्षों का गहन अध्ययन और उसके अनुसार खोजी दलों की सतर्कता बढ़ाए जाने की जरूरत है।

- इशरत अली कादरी, खानूगांव

गगनयान से उम्मीद

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा गगनयान मिशन एक मानव सहित अंतरिक्ष मिशन है, जिसके अंतर्गत चार अंतरिक्ष यात्रियों को तीन दिनों की अवधि के लिए अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। गगनयान मिशन के सफल होते ही भारत अंतरिक्ष में इंसान को भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। कहा जा सकता है कि नए युग का नया भारत नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पूर्व में चंद्रयान, आदित्य एल1 जैसे अंतरिक्ष अभियानों ने जहां भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की नींव को मजबूत किया है, वहीं आगामी वर्षों में द्वितीय मंगलयान और शुक्रयान-1 जैसे अंतरिक्ष अभियान इस नींव को और अधिक मजबूत करते दिखेंगे। गगनयान मिशन से सीधे तौर पर भारत और उसके विकास को बल मिलेगा।

- निखिल रस्तोगी, लखनऊ विवि

लापरवाही के हादसे

बढ़ती सुख-सुविधा की होड़ में लोगों की जिंदगी में व्यस्तताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। हर कोई समय को अपने मुट्ठी में रखने की कोशिश में है। हर किसी को जल्दी है। युवाओं को फर्राटे भरने में मजा आता है। कान में ईयरफोन लगा कर गीत-संगीत की मस्ती में जाते हुए वे कई बार मौत को भी गले लगा रहे हैं। सड़क पर दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करना भी दुर्घटना के कारण हैं। सबसे अधिक लोगों में यातायात को लेकर सलाहियत की जरूरत है। शराब पीकर या नशे का सेवन कर लोग सड़कों पर गाड़ियां चलाते हैं। इन हादसों का कारण मानवीय भूल बताया जाता है, मगर इसे लापरवाही और गलती भी कहा जाना चाहिए। बहुत कम दुर्घटनाएं वाहन की अचानक तकनीकी खराबी या अन्य कारणों से होती हैं। सतर्कता से हादसों के पीड़ितों की जान बचाई जा सकती है।

- प्रसिद्ध यादव, बाबूचक, पटना

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com